आर्थिक दृष्टिकोण, संभावनाएं और नीतिगत चुनौतियां

01
अध्याय

इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा एक ऐसे समय पर आ रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक माहौल में असामान्य खलबली मची हुई है। बाजार इस आशंका से डगमगा रहे हैं कि वैश्विक पुनरुद्धार लड़खड़ा रहा है जबकि चरम घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। निराशा से भरी इस पृष्ठभूमि में, भारत स्थिरता और अवसरों की आश्रय स्थली प्रतीत होता है। राजकोषीय समेकन और कम मुद्रास्फीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर टिकी इसकी वृहद अर्थव्यवस्था स्थिर है। इसका आर्थिक विकास विश्व की उच्चतम विकास दर वाले दशों की श्रेणी में शामिल है। इसमें सरकारी अवसंरचना के लिए बहुत जरूरी सरकारी व्यय की दिशा मोड़ने में मदद मिली है। ये उपलब्धियां सिर्फ इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल स्थितियों और लगातार दूसरे वर्ष कम वर्षा की पृष्ठभूमि में हासिल की गई है।

अब हमारे सामने यह काम है कि इन अनुकूल स्थितियों को मौजूदा अधिक कठिन वैश्विक माहौल में बनाए रखें। इसके लिए सावधानीपूर्वक आर्थिक प्रबंधन करना होगा। जहां तब मौद्रिक और नकदी नीति का संबंध है, मुद्रास्फीति के लिए लाभकर संभावनाएं, उत्पादन का बढ़ता अंतराल, विकास संभावनाओं को लेकर बनी अनिश्चितता और कारपोरेट क्षेत्र की अत्यधिक ऋणग्रस्तता, इन सबका अर्थ है कि इन नीतियों को सामान्य करने की गुंजाइश है। राजकोषीय समेकन अभी भी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए अनिश्चित वैश्विक माहौल में विकास बनाए रखते हुए, साख बनाए रखना और ऋण में कमी करना जरूरी होगा। सरकार के ''सुधार से परिवर्तन की ओर'' के मोर्चे पर अनेक उपाय किए गए हैं जो वर्धनकारी तो हैं लेकिन सामूहिक रूप से सार्थक हैं। इस बीच कुछ निराशा भी हाथ लगी है–विशेषकर वस्तु एवं सेवा कर के मामले में, जिस पर आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई किया जाना जरूरी है। केन्द्र में त्वरित संरचनागत सुधार, प्रतिस्पर्धी संघवाद की गतिशीलता और श्रेष्ठ आर्थिकी के श्रेष्ठ राजनीति होने के नाते, सब मिलकर उस बुनियादी सत्य को साकार कर सकते हैं जिसका नाम भारत है। अनिश्चित काल के लिए तो नहीं लेकिन फिलहाल, मजबूत राजनीतिक जनादेश द्वारा सृजित अनुकूल स्थिति, जिसे कमजोर वैदेशिक माहौल के चलते पुनः नया रूप दिया गया है, अभी भी लुभा रही है।

प्रस्तावना

1.1 एक वर्ष पहले, आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ''अनुकूल स्थिति'' की बात कही गई थी। यह माहौल मजबूत सरकारी जनादेश और अनुकूल वैदेशिक स्थितियों के मिश्रण से उपजा था। साथ ही, उसमें ''धमाकेदार'' सुधारों की असंभाव्य उम्मीदों के प्रति सजग भी किया गया था क्योंकि भारत में सत्ता का स्वरूप विविध है और साथ ही एक आवश्यक प्रेरक शक्ति–संकट का अभाव था। इसलिए उसमें ''सतत, सृजनात्मक और व्यापक वृद्धि'' के पक्ष में तर्क दिया गया था जो भावी कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक और अतीत के आकलन के लिए बैंचमार्क का काम करे।

1.2 इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा, असामान्य रूप से अस्थिर वैदेशिक माहौल की ऐसी पृष्ठभूमि में आ रही है जब अपेक्षाकृत कमजोर वैश्विक कार्यकलाप और चरम स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बड़े जोखिम खड़े हैं। परिणामस्वरूप संभावित प्रभावों के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना जाहिर सी आवश्यकता है। एक और आवश्यकता है-उम्मीदों को नए सिरे से तय करना।

1.3 यदि वैश्विक अर्थव्यस्थाएं संकटग्रस्त हो जाती हैं अथवा और कमजोर पड़ती हैं तो भारत के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वैश्विक और भारतीय विकास के बीच सह-संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं (चित्र 1)। इसलिए आगामी वर्ष में भारत के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन सीमाओं में रहकर किया जाना होगा। यह भावी निष्पादन के लिए अग्रिम में सफाई देने के बराबर नहीं हैं, बल्कि यह विश्व के साथ भारत के "अधिकाधिक जुड़ जाने" की गंभीर सच्चाई है।

1.4 पीछे देखें तो स्पष्ट प्रश्न यही है : अर्थव्यथवस्था ने पिछले वर्ष की समीक्षा में निर्धारित मानकों पर कैसा काम किया है? भारत के आर्थिक कार्यनिष्पादन को विशिष्ट बैंचमार्कों से मापा जा सकता है: भारत बनाम अन्य देश; और भारत बनाम इसकी अपनी मध्यावधिक क्षमता। पहले बैंचमार्क पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है; और दूसरे बैंचमार्क पर सतत प्रगति हो रही है तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की अभी भी गुंजाइश है।

1.5 चलिए, अन्य देशों के साथ तुलना से शुरूआत करते हैं। ऐसे समय पर, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य स्थिति हलचल और अस्थिरता की है, वहीं भारत स्थिरता और अवसरों के देश के रूप में उभरा है। इसकी बृहत अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसके 2016 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की संभावना है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, जहां कमजोर वैश्विक मांग और निजी निवेश कम होने के कारण निर्यात में कमी आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

1.6 आंशिक रूप से, यह कार्यनिष्पादन अनेक सार्थक सुधारों के कार्यान्वयन को दर्शाता है जो वर्धनकारी होते हुए भी सामूहिक दृष्टि से सार्थक हैं,

- एक स्पष्ट और व्यापक माहौल तैयार करना कि केंद्र में भ्रष्टाचार की समस्या का सार्थक समाधान कर लिया गया है, यह सरकारी आस्तियों की नीलामी में पारदर्शिता और विनियामक निर्णयों में हस्तक्षेप न करने के रूप में प्रतिबिंबित होता है;
- सभी क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को उदार बनाना जिसमें चिरप्रतीक्षित बीमा विधेयक को पारित करना भी शामिल है। एफडीआई सुधार निर्णायक रूप से सैद्धांतिक परिवर्तन दर्शाते हैं जिसमें अब एफडीआई को मात्र बरदाश्त किए जाने योग्य मजबूरी न समझकर अब स्वागत किए जाने योग्य माना जा रहा है;

चित्र 1: 1991 से भारत और विश्व की विकास दर (प्रतिशत)

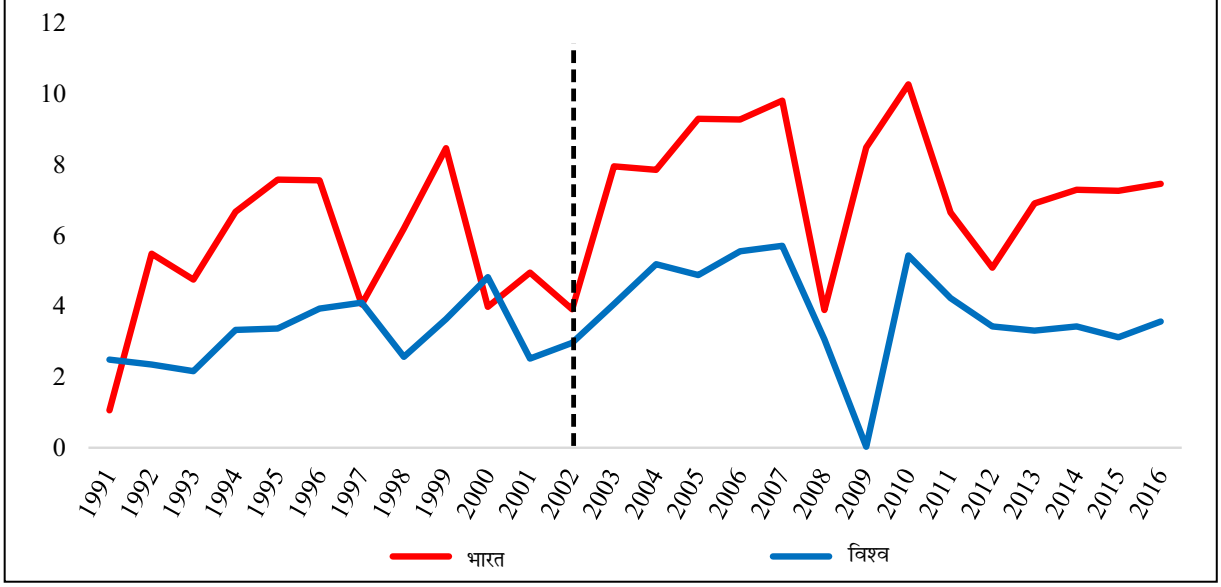

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यू ई ओ) जनवरी, 2016 अपडेट

- कारोबार करने में आसानी लाने के लिए जबरदस्त प्रयास करना, जिसके कारण भारत विभिन्न देशों में स्पर्धात्मकता की रैंकिंग में आगे बढ़ा है और स्टार्ट-अप तथा ई-कॉमर्स के क्षेत्रों की अप्रत्याशित गतिशीलता और रोजगार सृजन करने वाली बड़ी कंपनियों के हित में दिखाई दे रही "लाखों क्रांतियों" के लिए महत्वपूर्ण अनुभव बन गया (संभावना भाग में बॉक्स 1.4)
- कर संबंधी निर्णयों में स्थिरता और संभाव्यता जो विदेशी कंपनियों पर लगाए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के निपटारे में दर्शाई जाती है, को पुन: स्थापित करना और उस सीमा में पर्याप्त वृद्धि करना, जिस सीमा के बाद कर विभाग अपील फाइल करेगा;
- देश की अवसंरचना क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और निजी निवेश के अभाव को पूरा करने के लिए एक बड़ा सरकारी निवेश कार्यक्रम कार्यान्वित करना;
- प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने के लिए किसानों को सुरक्षा देने हेतु एक बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू करना;
- खेत संबंधी दखल कार्रवाई को सीमित करना जिससे समग्र मुद्रास्फीति पर काबू पाने का बड़ा अच्छा असर हुआ;
- 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिए कुछ ही महीनों में बैंक खाते खोलकर जनधन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को मिशन मोड में परिवर्तित किया गया। वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम को 11 भुगतान बैंकों और 10 छोटे बैंकों की लाइसेंसिंग से भी बढ़ावा दिया जाएगा;
- युगांतरकारी जैम (जनधन आधार मोबाइल) त्रिसूत्र के कार्य को बढ़ाना। एलपीजी के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू किया गया जिसमें लगभग 151 मिलियन लाभानुभोगियों ने अपने बैंक खातों में कुल 29,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्ति की। इस आधार पर जैम त्रिसूत्र अन्य सरकारी कार्यक्रमों और सब्सिडियों पर भी लागू किया जाएगा;
- अनेक क्षेत्रों जैसे खुले में मल त्याग और स्वैच्छिक आधार पर सब्सिडी छोड़ने के संबंध में सामाजिक मानदंडों को बदलने का प्रयास किया गया;
- विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार शुरू किए गए (विशेषकर उदय योजना); और
- नीतियों के उलटाव से बचने का प्रयास।

1.7 फिर भी, धारणा यह थी कि मात्रा गुणवत्ता को दोषमुक्त नहीं कर सकती, यह भी कि योजनाओं को शुरू करना और बेहतर कार्यान्वयन नीतिगत परिवर्तनों की तुलना में विशेषाधिकृत था और भारत की आपूर्ति क्षमता से पूरा लाभ उठाने के लिए बनाई गई नीतियों को अधिक उत्साह से आगे बढ़ाया जा सकता था। यह धारणा आंशिक रूप से सभी अलग-अलग सुधारों को संयुक्त रूप देने की असफलता और इसलिए टुकड़ों की बजाय समग्र रूप को समझने की असफलता के कारण थी। लेकिन ये सामने आई कुछ निराशाओं के कारण भी थी।

1.8 युगांतरकारी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक का अनुमोदन अभी दूर है; विनिवेश कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है, इसमें स्ट्रैटजिक बिक्री के लक्ष्य हासिल न किया जाना भी शामिल है; और सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने का अगला चरण चल रहा है। परेशानी यह भी है कि कारपोरेट और बैंक तुलनपत्र अभी भारग्रस्त हैं जिससे दीर्घावधिक विकास का महत्वपूर्ण प्रेरक, निजी निवेश का, पुनरूद्धार करने की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।

1.9 शायद बुनियादी चिंता इस बात की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है। यह बात निश्चित है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। *देश की दीर्घावधिक संभावित विकास दर अभी भी लगभग 8-10 प्रतिशत है।* (बॉक्स 1.1 में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है)। इस संभावना को साकार करने के लिए कम से कम तीन मोर्चों पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

1.10 पहला, भारत स्वाभाविक रूप से बाजार विरोधी और निष्पक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप का समर्थक होने की स्थिति से हटकर, अब उद्यमिता के पक्ष में और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवादी होता जा रहा है। लेकिन उद्योग के पक्ष में होने का अर्थ यह है कि हम वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धा का समर्थन करें। कारपोरेट सब्सिडियां तथा व्यापक पुरानी छूटें यह रेखांकित करती हैं कि क्यों कारोबार का समर्थन (न कि बाजारों का) वस्तुत: प्रतिस्पर्धा में बाधा बन सकता है। इसी प्रकार, सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवाद निश्चित रूप से इसे कम किए जाने में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसकी मूल भूमिकाओं का महत्व कम किए बिना और वस्तुत: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे मजबूत भी करके संभव होगा।

1.11 अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल सृजित करने की कुंजी

यही होगी कि (चक्रव्यूह से) प्रस्थान करने की समस्या का समाधान किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समस्या से ग्रस्त है और निवेश, कार्यदक्षता, नौकरियों के सृजन और विकास में इसे एक रूकावट के रूप में बरदाश्त कर रही है (देखें अध्याय 2)। भारतीय अर्थव्यवस्था सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से हटकर, बिना प्रस्थान वाले बाजार वाद में दाखिल हो गई है। सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है जैसे नया दिवालिया कानून, बंद पड़ी परियोजनाओं को पुनः चालू करना और सरकारी निजी भागीदारी संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार करना, जिससे प्रस्थान करने में मदद मिल सकती है और अर्थव्यवस्था की क्षमता में सुधार होगा।

1.12 दूसरे, आम जन में – उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया जाना जरूरी होगा ताकि भारत की आबादी का लाभ उठाया जा सके। भविष्य का कामगार आज का बालक या भ्रूण है जो आज की माताओं द्वारा पाला-पोसा जाएगा। जाहिर है, माता और शिशु, पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसमें मातृ स्वास्थ्य और जीवन के आरंभ में की गई दखल कार्रवाई शामिल है और यह अध्याय 5 का विषय है। मानव पूंजी में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के संबंध में अध्याय 7 में चर्चा की गई है।

1.13 मोटे तौर पर कहें तो आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी एक भारी भरकम चुनौती है। संसाधनों के अधिकाधिक अंतरण से राज्यों को सेवा सुपुर्दगी की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और कार्यदक्षता में सुधार लाना होगा। इसके लिए उन्हें अपना ध्यान परिव्यय से हटाकर परिणामों पर केंद्रित करना होगा और मॉनीटरिंग, नवपरिवर्तन करके तथा गलतियां करके भी सबक लेने होंगे।

1.14 चौदहवें वित्त आयोग के बाद, सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए केंद्रीय और राज्यों की सापेक्ष भूमिकाओं में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है: केंद्र को नीतियों में सुधार लाने, विनियामक संस्थाओं को मजबूत बनाने और सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को संभव बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जबकि राज्यों को बेहतर सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करने पर मेहनत करनी होगी।

1.15 तीसरे, हालांकि सेवा और विनिर्माण जैसे गतिशील क्षेत्रों पर सबका ध्यान जाता है, फिर भी भारत अपने कृषि क्षेत्र को उपेक्षित करने की स्थिति में नहीं है (अध्याय 4)। आखिरकार, भारतीय परिवारों का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा अपनी आमदनी का अधिकांश खेती से प्राप्त करता है। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक खास तौर पर उत्पादकता, मौसम और बाजार के झटकों, जो उनकी आमदनी पर असर डालते हैं, के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में शुरू की गई फसल बीमा योजना से काफी हद तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा।

1.16 जलवायु परिवर्तन और उभरती कमी की स्थिति से ''कम के लिए अधिक'' पर ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाएगा और इस तरह प्रोत्साहनों और सब्सिडियों की मौजूदा प्रणाली, जिसमें मृदा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर डालने वाले उर्वरक, जल और विद्युत जैसी निविष्टियों के अधिक प्रयोग का बढ़ावा दिया जाता है, पर भी विचार किया जाना होगा। यह निविष्टियां अमीर और बड़े किसानों को जरूरत से ज्यादा लाभान्वित करती हैं।

1.17 अनेकानेक चुनौतियों के बावजूद, अभी भी आशा की किरण बाकी है। यह आशा प्रतिस्पर्धी संघवाद की गतिशीलता से उपजी है। अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्य अधिकाधिक ''मॉडल और आकर्षक गंतव्य'' बनते जा रहे हैं। किसी एक राज्य में किए गए सफल प्रयोग अन्य राज्यों के लिए उन्हें दोहराए जाने के लिए मॉडल बन जाते हैं, यह दिखाकर कि क्या किया जा सकता है और इस तरह काम न करने या कम करने के बहाने बेकार हो जाते हैं। वे आकर्षक गंतव्य इसलिए भी है क्योंकि वे फिसड्डी राज्यों को परे करके, संसाधन, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी आकर्षित करते हैं जिससे ''प्रस्थान'' के जरिए परिवर्तन संभव हो पाता है।

1.18 इस आशावाद की पिछले दशक की घटनाओं से भी पुष्टि होती है कि जिनसे इस धारणा को बल मिला है कि अच्छी आर्थिकी ही अच्छी राजनीति है, भले ही बार-बार होने वाले चुनाव नीति निर्माण के कार्य को पेचीदा बना देते है। ऐसा हमेशा और हर जगह नहीं होता, लेकिन फिर अब अधिकाधिक ऐसी केंद्र और राज्य सरकारों, जिन्होंने तीव्र विकास और सुशासन की व्यवस्था की है, उन्हें दोबारा चुना जाता है तथा विलोमतः भी स्थिति यही है। मिसाल के तौर पर, यह स्पष्ट है कि जो राज्य सरकारें तीन बार चुनी गई हैं, वे वहीं हैं जिन्होंने तीव्र कृषि विकास किया है।

1.19 इसके अलावा, यह आशा भारत की निर्णय

लेनी की प्रक्रिया से भी उपजी है जो निराशाओं से उबरने की शक्ति, और दबाव पैदा करती है। वस्तु एवं सेवा कर अभी भी हमारी पहुंच में है; नई दिवालियापन प्रक्रियाएं और डाभोल जैसे कुछ बड़ी रुकी हुई परियोजनाओं का पुनरुद्धार दर्शाता है कि प्रस्थान की समस्या का समाधान किया जा सकता है; युगांतरकारी जैम त्रिसूत्र कार्य के लिए निर्मित की जा रही अवसंरचना न केवल एक सच्चाई बन रही है बल्कि देश भर में अन्य मौन क्रांतियां हो रही हैं – उत्तर प्रदेश में चीनी और बीज, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में खाद्य पदार्थ और मिट्टी का तेल – जो बढ़ती हुई जैम त्रिसूत्र के सपने को साकार कर रही हैं (अध्याय 3 में वर्णित)।

1.20 कुल मिलाकर, हमेशा के लिए नहीं लेकिन फिलहाल तो, भारत के लिए वह ''अनुकूल स्थिति'' अभी भी मौजूद है।

बॉक्स 1.1 : भारत की संभावित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है?

भारत में अपार संभावनाएं हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसे मापा जा सकता है?

विशिष्ट रूप से अर्थशास्त्री किसी देश की संभावित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को दो तरीकों से मापते हैं: पहले, विगत विकास से निष्कर्ष निकाल कर और दूसरे विकास के बुनियादी संचालकों: पूंजी (वास्तविक और मानव), श्रम और उत्पादकता का अनुमान लगाकर। दोनों तरीकों की अपनी सीमाएं हैं और दोनों ही अनेक अनुमानों का सहारा लेते हैं।

पहले तरीके के अनेक रूप हैं जिसमें हॉड्रिक-प्रेसकॉट फिल्टर का प्रयोग शामिल है। लेकिन ये सब मूलत: यांत्रिक हैं और वस्तुत: विगत की विकास दरों का कुछ भारित औसत हैं। इस तरीके का एक नुकसान यह है कि वास्तविक विकास में हुई घटबढ़ संभावित विकास के अनुमानों में काफी अस्थिरता ला सकती है। लेकिन जब तक बुनियादी नीति और संस्थागत माहौल में कुछ आमूल परिवर्तन नहीं किए जाते, संभावित विकास अपेक्षाकृत स्थिर रहना चाहिए।

विकास के बुनियादी निर्धारकों का अनुमान करके संभावित सकल घरेलू उत्पाद के आकलन (जैसाकि रोड्रिक और सुब्रह्मणियन, "Why India Can Grow at 7 Per Cent a Year or More"] EPW [2004]) में कुल कारक उत्पादकता वृद्धि के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं, जो कि मनमाने हो सकते हैं, जब तक वे विगत कार्यनिष्पादन पर आधारित न हों, जिससे उपर्युक्त समस्याएं हो सकती हैं।

संभावित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाने का एक और तरीका गहन निर्धारकों और समाभिरूपता फ्रेमवर्क का प्रयोग करना है। इस संबंध में सुस्थापित साहित्य तैयार हो चुका है (North, D, "Institutions", Journal of Economic Perspectives, [1991], Acemoglu, D and J.A. Robinson, "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty," Crown Business [2012]) जिनसे पता चलता है कि संस्थाएं दीर्घावधिक विकास के लिए मुख्य निर्धारक हैं। यह बात नीचे दिए चित्र1 में दिखाई गई है।

चित्र 1 : संस्थाओं का महत्व है

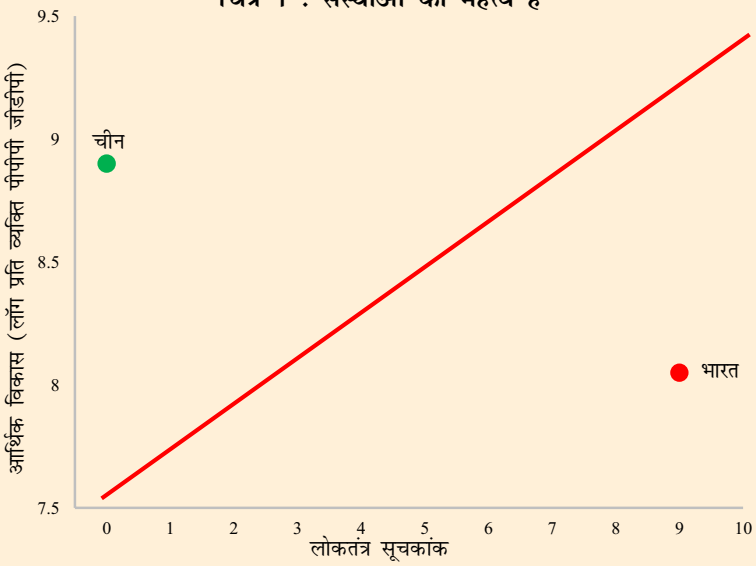

जारी....

चित्र में ऊपर की ओर जाती रेखा राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक विकास के बीच मजबूत संबंध (औसतन) जो अनुभव जन्य अनुसंधान में देखा गया है, को दर्शाती हैं और जिससे ''संस्थागत महत्व'' की अवधारणा का केंद्रीय तर्क सिद्ध होता है। तथापि, चीन और भारत इस संबंध में बाहर खड़े हैं (वे सर्वोत्तम स्थिति की रेखा से कहीं दूर हैं)। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से प्रत्येक देश इस संबंध को लेकर एक अपवाद है, बल्कि चुनौती ही है लेकिन विपरीत तरीके से। भारत (जो रेखा से कहीं नीचे है) इसकी निश्चित रूप से गतिशील राजनीतिक संस्थाओं के कारण पर्याप्त समृद्ध नहीं है। चीन (जो रेखा से कहीं ऊपर है) अपनी कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं के चलते बहुत समृद्ध है।

अनुमान यह है कि भारत और चीन इस औसत से पलट जाएंगे, अर्थात वह अधिक सामान्य हो जाएंगे और मध्यावधिक संदर्भ में सर्वोत्तम स्थिति की रेखा की ओर मुड़ेंगे। औसत उलटाव अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। चीन के संबंध में अनुमान यह है कि ''सामान्य'' देश बनने की यह प्रक्रिया धीमी विकास दर और तीव्र लोकतंत्रीकरण के जरिए होगी जैसाकि चित्र 2 में दिखाया गया है। सच तो यह है कि चीन के विकास में आई मंदी असामान्य रूप से उच्च विकास की अवधि के बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखी जानी चाहिए। भारत के संबंध में सामान्यीकरण को विकास दर में वृद्धि का रूप लेना चाहिए जैसाकि नीचे चित्र में दिखाया गया है।

इस तरह भारत की संभावित विकास दर ऐसी स्थितियों के उलटाव के रूप में आकलित की जा सकती है जहां इसका आर्थिक विकास सुविकसित आर्थिक संस्थाओं के अनुरूप है। सवाल यह है कि अंतर्निहित विकास दर क्या है जो औसत उलटाव के अनुरूप है।

चित्र 2: विकास का सामान्यीकरण – चीन और भारत

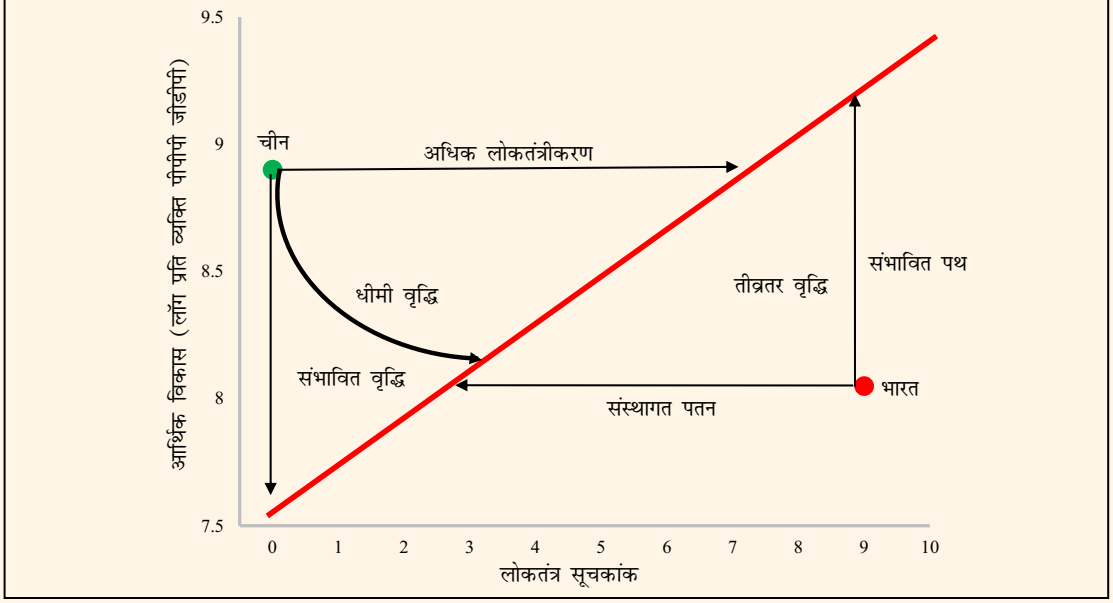

बुनियादी समाभिरूपता फ्रेमवर्क सामान्यीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान भारत की संभावित विकास दर का अनुमान, भले ही मोटे तौर पर लगाने के लिए फ्रेमवर्क की व्यवस्था करता है (इस परिकलन के लिए सामान्यीकरण बीज गणित हेतु तकनीकी परिशिष्ट देखें)।

समाभिरूपता सिद्धांत के अनुसार, 2015 और 2030 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (पीपीपी संदर्भ में), 2015 में संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आरंभिक स्तर में अंतर का कुछ गुणज होना चाहिए। यह अंतर लगभग 2.2 लॉग प्वाइंट है। इस गुणज को समाभिरूपता गुणांक कहा जाता है – वह दर जिस पर भारत संयुक्त राज्य अमरीका के साथ मुकाबला करेगा। उपलब्ध साहित्य से एक उचित मानदंड यही मिलता है कि यह कम से कम उन देशों के लिए, जो समाभिरूप हो रहे हैं, लगभग दो प्रतिशत प्रतिवर्ष होना चाहिए। पूर्वी एशियाई देश कहीं तेज रफ्तार पर समाभिरूप हुए लेकिन अन्य देश धीमी रफ्तार पर समाभिरू हो रहे हैं।

ऊपर दिखाए चित्र का महत्व इस बात में है कि चूंकि भारत ने अभी तक अपेक्षित स्तर से कम उपलब्धि की है, इसलिए इसे सामान्य से अधिक तेज रफ्तार पर समाभिरूप होना चाहिए ताकि यह ''सामान्य'' रेखा तक पहुंच सके। इसलिए इसका समाभिरूपता गुणांक 2 प्रतिशत से कहीं बेहतर होना चाहिए। इन पीपीपी विकास दरों को बाजार मुद्रा दर के विकास दरों में रूपांतरित किया जाना चाहिए। परिणामी अनुमान इस समाभिरूपता गुणांक के बारे में वैकल्पिक धारणाओं के संबंध में नीचे सारणी में दिखाए गए हैं।

इस विश्लेषण के आधार पर, भारत की मध्यावधिक विकास संभावना 8 और 10 प्रतिशत के बीच है। बेशक, यह उस संभावना का एक

जारी....

अनुमान है जो अवसरों की उपलब्धता का संकेत देता है। अवसर को सच्चाई में बदलने के लिए कठोर नीतिगत निर्णय लेने और सहयोगी वैदेशिक माहौल की जरूरत होगी।

सारणी : चीन और भारत की संभावित विकास दर, 2015-30 (प्रतिशत)

समाभिरूपता की रफ्तार (प्रतिशत)	चीन	भारत
2	3.3	6.2
2.5	4.1	7.6
3	5.0	9.0
3.5	5.9	10.4

स्रोत: वित्त मंत्रालय के परिकलन

वैश्विक संदर्भ

1.21 एक वर्ष पहले प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा और बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद से, भारतीय अर्थव्यस्था ने बृहत आर्थिक स्थिरता बहाल करने में हासिल उपलब्धियों को समेटना जारी रखा। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू लेखा घाटा में गिरावट हुई है जिसके चलते खलबली के इस दौर में भारत सापेक्ष बृहत स्थिरता का आश्रय स्थल बन गया है। आर्थिक विकास में पुनरूद्धार दिखाई दे रहा है, भले ही वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रफ्तार पर हो।

1.22 साथ ही, आगामी बजट और 2016-17 (वित्त वर्ष 2017) की आर्थिक नीति को मोटे तौर पर असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण और कमजोर वैदेशिक माहौल का सामना करना होगा। हालांकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक बार फिर यह अनुमान लगा रही हैं कि वैश्विक विकास अपने मौजूदा मंद स्तर से उबरेगा, फिर भी उनका यह मूल्यांकन है कि गिरावट के जोखिम अभी भी बरकरार हैं। ये अनिश्चित और कमजोर संभावनाएं भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन के कार्य को पेचीदा बना देंगी।

1.23 इन जोखिमों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े वित्तीय संकट अब बार-बार आ रहे हैं। 1982 के लैटिन अमरीकी ऋण संकट, 1990 के दशक के अंत में आए एशियाई वित्तीय संकट और 2008 के पूर्वी यूरोपीय संकट ने इंगित किया कि ये संकट हर दशक में एक बार आ रहा है। लेकिन ये संकट, जिनकी शुरूआत 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से हुई और यह आगे बढ़कर दीर्घकालीन यूरोपीय संकट तक जा पहुंचा, 2013 के छोटे-छोटे संकट और 2015 में चीन की मेहरबानी से मची खलबली – इनसे पता चलता है कि इन घटनाओं के बीच अब अंतराल कम होता जा रहा है।

1.24 इस पूर्वधारणा को निकट भविष्य में सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि कम से कम तीन बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं – चीन, ब्राजील, सऊदी अरब – में स्पष्ट कमजोरियां मौजूद हैं। यह एक ऐसे समय पर हो रहा है जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी विकास और उत्पादकता की वृद्धि नरम पड़ी रही है (देखें बॉक्स 1.2)। तथापि, अधिक लचीली विनिमय दरें भारी संकटों को कुछ कम कर सकती हैं लेकिन अस्थिरता दीर्घकालीन होगी।

1.25 एक पश्च जोखिम परिदृश्य जिसके लिये भारत को योजना बनानी चाहिये, वह है चीन में समान समायोजन के दृष्टिगत एशिया में प्रमुख मुद्रा पुनर्समायोजन, क्योंकि ऐसी किसी भी घटना से पूरे विश्व में अपस्फीति फैल जाएगी। दूसरा, पश्च जोखिम परिदृश्य का प्रकटन नीतिगत कार्यों-अर्थात् बड़े उभर रहे बाजार वाले देशों से बहिर्वाह पर काबू पाने के लिये किये गये पूंजीगत नियंत्रण के परिणाम जो उनसे उत्सर्जित विकास गति को और भी मंद कर देंगे।

1.26 इनमें से किसी भी मामले में, विदेशी मांग कमजोर होने की संभावना है, जिससे भारत-अल्पावधि संदर्भ में-वृद्धि संवेग को कमजोर होने से रोकने के लिये मांग के घरेलू स्रोत तलाशने और उन्हें सक्रिय

करने को विवश होगा। कम से कम, पश्च जोखिम घटना से भारतीय मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति को विदेशी अवस्फीतिक संवेग से न जुड़ना आवश्यक हो जाएगा। तसल्ली यही होगी कि तेल और वस्तुओं की निम्नतर कीमतें मुद्रास्फीति और दोहरे घाटे पर रोक लगाने में सहायक होंगी।

बॉक्स 1.2: विगत और भावी वित्तीय संकट का विश्लेषणपरक वर्गीकरण

1980 से, वैदेशिक वित्तीय संकटों ने तीन बुनियादी रूपों में से एक का अनुगमन किया है : लेटिन अमेरिकी, एशियाई वित्तीय संकट (एएफसी), अथवा वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) मॉडल। इसलिए यह पूछा जा सकता है कि: एक व्यवस्थित रूप से उभर रहे बाजार में यदि ऐसी कोई प्रमुख अप्रत्याशित घटना हुई तो यह इनमें से किस रूप का अनुगमन करेगी? उत्तर यह है कि संभवत: उपर्युक्त में से किसी का नहीं। इसके निहितार्थ विगत 80 वर्षों में देखी गई किसी घटना की तरह नहीं होगे। (संलग्न तालिका में सार दिया गया है)।

लैटिन अमेरिकी ऋण संकट में, सरकारों ने अपनी विनिमय दरें निर्धारित करते समय विदेशी उधारी (पुनर्चक्रित पेट्रो डालर की)द्वारा वित्त पोषित अत्यधिक व्यय शुरू किया। इस खर्च से एक क्लासिक क्रम शुरू हुआ: आर्थिक अधितापन, बृहत चालू खाता घाटा जिसका वित्त पोषण कदाचित कठिन सिद्ध हुआ, और अंतत: विदेशी उधारी में चूकें हुई। 1991 का भारतीय वैदेशिक संकट इस श्रेणी से संबंधित था, हालांकि देश ने कभी चूक नहीं की।

1990 के अंत के एएफसी में, पारेषण तंत्र इसी प्रकार का था, अर्थात् नियत विनिमय दरों के अंतर्गत अधितापन और अस्थिर वैदेशिक स्थितियां-किन्तु उत्प्रेरक संवेग सरकारी उधारी की अपेक्षा निजी उधारी था। 2008 में पूर्वी यूरोप की समस्याएं इसी श्रेणी से संबंधित थीं। फेडरल रिजर्व के ''अमेरिकी राजकोष में उछाल" के बाद उभर रहे अनेक बाजारों में 2013 में आया लघु संकट एशियाई संकट की तरह ही था। इसमें यही अंतर था कि इसमें प्रभावित देशों के पास अधिक लोचनीय विनिमय दरें थीं जिनकी वजह से नियत व्यवस्थाओं के विफल होने पर होने वाले व्यापक विध्वसंक परिवर्तनों का निराकरण हो गया।

2008 का जीएफसी, जिसका केन्द्र बिन्दु अमेरिका था, एक विलक्षण संकट था क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण देश शामिल था और इससे उसकी वित्तीय प्रणाली के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया था। इनका प्रभाव वैश्विक रूप से पडा, विडंबना यह रही कि ये समस्याएं अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में उत्पन्न होने पर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर पूंजी की बाढ़ सी आ गई, जिससे डॉलर मूल्य में तेज गति से वृद्धि हुई और उभर रहे बाजारों में मुद्रा का पर्याप्त अवमूल्यन हुआ। इस तरीके से, जी एफ सी, ने शेष विश्व पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव को निष्प्रभावी करने के साथ-साथ एक ऐसे समायोजन तंत्र की स्थापना की जो संकट पर काबू पाने में उभर रहे बाजारों के लिये सहायक हुआ।

जापानी संकट पारेषण तंत्र (इक्विटी बाजारों और रियल इस्टेट को दायरे में लेते हुये आस्ति मूल्य में हल्के उछाल) के समान था। लेकिन यह इस अर्थ में भिन्न था कि घरेलू उधार की बजाय कारपोरेट उधार ने इसे प्रेरित किया। इस संकट का कोई व्यवस्थागत वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ा, क्योंकि जापान एक प्रमुख अंतरर्राष्ट्रीय बैंकिंग केन्द्र भी नहीं था। इसका वैश्विक निर्यातों पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, यद्यपि जापान एक प्रमुख वैश्विक व्यापारी था (और है), क्योंकि जी एफ सी में, संकट अपने आप समाप्त हो जाने के कारण अधिकेन्द्र की मुद्रा में सुधार हुआ था।

चीन की मौजूदा स्थिति भी ए एफ सी मामले की ही तरह है। उसमें धीमी वृद्धि के संदर्भ में अत्यधिक कार्पोरेट ऋण की आशंका है तथा बदल रहा आर्थिक प्रबंधन वृहत पूंजीगत बहिर्वाह को प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन परिणाम कम ही सुनिश्चित है, क्योंकि जहां एशियाई देशों के पास सीमित विदेशी मुद्रा भंडार था, वहीं चीन की अधिकारिक आस्तियां 3 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है जो वर्षों से इसके विशाल चालू खाता अधिशेष के कारण है। यह स्थिति चीन को अपनी आरंभिक समस्याओं से निपटने, और इसके परिणामों को न्यूनतम करने, उदाहरणार्थ, विनिमय दर में हानिकारक कमी की अपेक्षा क्रमिक कमी की अनुमति देकर, की कहीं अधिक गुजाइंश और समय प्रदान करती है।

चाहे कोई घटना चीन अथवा दूसरे विशाल उभर रहे बाजार में घट जाए, फिर भी यह उपर्युक्त तीन श्रेणियों की घटना से पूर्णत: भिन्न होगी। इसमें किसी ऐसे व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण देश में विशाल मुद्रा अवमूल्यन शामिल होने की संभावना होगी जो शेष विश्व, खासकर ऐसे प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों, के लिये अवस्फीतिकारी/प्रतिस्पर्धात्मक आघात के रूप में बाहर फैलेगी। इसके परिणामस्वरूप, जी एफ सी में समायोजन तंत्र का निर्माण होगा-जिसमें संकट वाले देश की मूल्यांकित मुद्रा का अभाव होगा।

इस विचार से, व्यवस्थागत रूप से उभर रहे बाजार में संभावित पश्च घटना 1930 की घटनाओं के अधिक समान होगी, जब यूके और तत्कालीन यूएस ने स्वर्ण का मानक छोड़ दिया था जिससे अन्य देशों ने अवमूल्यन की शुरूआत कर दी थी, जिससे वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप धराशाई हो गया था ।

तालिका: वैदेशिक वित्तीय संकट का विश्लेषण और वर्गीकरण

संकट का प्रकार	उत्पन्न कारक देश	समस्या का उद्गम	प्रस्फुटन	कारण	विनिमय दर प्रणाली	अभ्युक्ति
लैटिन अमेरिका	उभरते बाजार (लेटिन अमेरिका 1982, भारत 1991); छोटे उन्नत देश(यूनान) 2010 से आगे	सरकारी उधारी	चालू खाता घाटा	काल्पनिक आक्रमण और विनिमय दर धराशाई हुई	नियत दर	यूनान यूरो का हिस्सा था, अत: इस कारण ब्याज दरों तीव्र वृद्धि हुई
एशियाई वित्तीय संकट	उभरते बाजार (पूर्वी एशिया, 1997-99, पूर्वी यूरोप 2008, फ्रेजाइल फाइव-2013), लघु और उन्नत देश (स्पेन 2010)	कार्पोरेट उधारी	आस्ति मूल्य में अस्थिरता; उच्च कार्पोरेट लाभ	"पूंजीगत प्रवाहों की" अचानक बंदी: और विनिमय दर ध राशायी हुई	नियत दर	फ्रेजाइल फाइव में मुद्रा दरें लोचनीय थीं, स्पेन यूरो का हिस्सा था।
जापान	व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण	कार्पोरेट उधारी	आस्ति मूल्य में अस्थिरता; उच्च कॉर्पोरेट लाभ	आस्ति मूल्य धराशाई हो गया	विनिमय दरों में घट -बढ़	संकट के बाद येन में सुधार हुआ
वैश्विक वित्तीय संकट	व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण (यूएस 2008)	बैंक और उपभोक्ता उधारी	आवास के आस्ति मूल्य में अस्थिरता	आस्ति मूल्यों में सुधार	लोचनीय विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर में सुधार हुआ
दी नेक्स्ट	व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण	कॉर्पोरेट उधारी	ऋण बढ़ना, आस्ति मूल्य में अस्थिरता	विनिमय दर में तीव्र गिरावट के साथ, अचानक बंदी की संभावना	घट-बढ़ को व्यवस्थित किया	संकट वाले देश की मुद्रा का अत्यधिक अवमूल्यन हो सकता था।

भारतीय संदर्भ

1.27 भारतीय अर्थव्यवस्था बृहत आर्थिक स्थिरता को बहाल करने में पर्याप्त लाभों को समेकित करती रही है। इस पुनरुद्धार को देशों के बीच तुलना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गत वर्ष की समीक्षा में, हमने बृहत आर्थिक दोषों का समग्र सूचकांक तैयार किया था, जिसमें किसी देश के राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे, और मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। इस सूचकांक से पता चलता है कि 2012 में भारत प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों में सर्वाधिक कमजोर था। तत्पश्चात्, भारत ने अपनी वृहत-कमजोरियों को कम करने में सर्वाधिक जबरदस्त प्रगति की है। 2013 से, इसके सूचकांक में 5.3 प्रतिशतांक का सुधार हुआ जबकि चीन का सूचकांक 0.7 प्रतिशतांक रहा, भारत के निवेश श्रेणी वाले सभी देशों के लिये 0.4 प्रतिशतांक रहा। ब्राजील के मामले में 1.9 प्रतिशतांक की गिरावट रही है। (चित्र 2)

1.28 यदि वृहत आर्थिक स्थिरता निवेशकों के लिये किसी देश के आकर्षण का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो इसकी विकास दर दूसरा। गत वर्ष की समीक्षा में हमने एक साधारण तर्कसंगत निवेशक मूल्यांकन सूचकांक (आर आई आर आई) तैयार किया था, जिसमें दो घटक शामिल थे, रिवार्डो के लिये मानदंड के रूप में विकास तथा जोखिमों के लिये एवजी बृहत-आर्थिक सुभेद्यता सूचकांक। यह आर आई आर आई चित्र 3 में दिया गया है; उच्चतर स्तर बेहतर निष्पादन दर्शाते हैं। यह दृष्टव्य है कि भारत न केवल सूचकांक में परिवर्तन के दृष्टिगत बेहतर कार्य करता है, अपितु स्तर की दृष्टि से भी बेहतर कार्य करता है, जो बी बी बी - निवेश ग्रेड में इसकी उत्कृष्टता तथा ए ग्रेड[1] में इसकी 'बेहतरी' की अनुकूल रूप से तुलना करता है। एक निवेश गंतव्य के रूप में, भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर श्रेष्ठ देश है।

1 फिच रेटिंग ऐजेन्सी के अनुसार भारत बी बी बी निवेश श्रेणी में है। ए श्रेणी इससे ठीक ऊपर है।

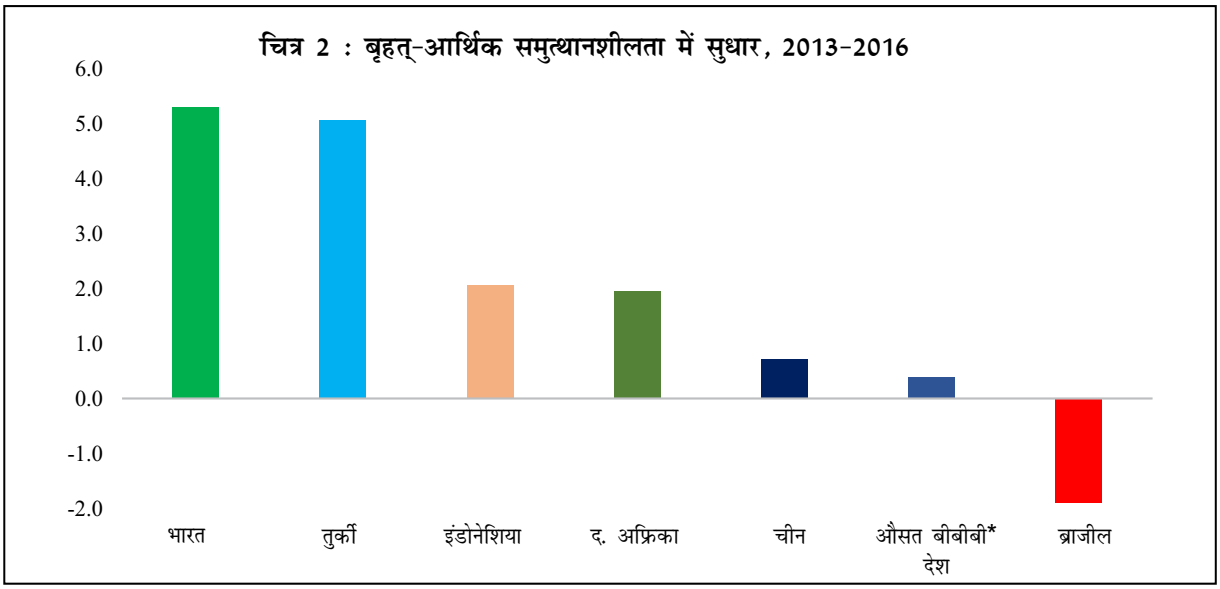

स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ, अक्तूबर 2015 और जनवरी 2016 अपडेट
*बीबीबी फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार उन देशों का वर्गीकरण है जिसमें भारत शामिल है।

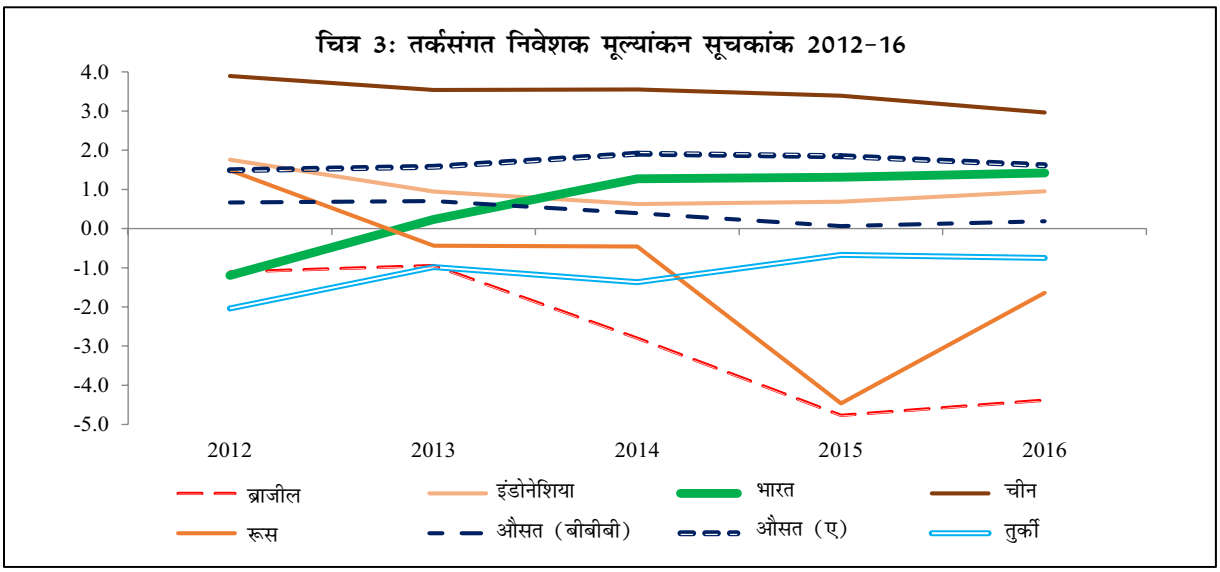

स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ, अक्तूबर 2015 और जनवरी 2016 अपडेट

प्रमुख घटनाक्रमों की समीक्षा

1.29 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हालिया जारी सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों में, स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2014-15 में 7.2 प्रतिशत से 2015-16 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय की गति का तेज होना है इसी प्रकार जोड़े गये सकल मूल्य (जी वी ए) की वृद्धि दर 2014-15 में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 के लिये 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है (चित्र 4 (क) और (ख)। हालांकि कमजोर मानसून के कारण एक क्रम में दूसरे वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में निम्न वृद्धि दर्ज हुई है किन्तु गतवर्ष की तुलना में इसकी स्थिति बेहतर हुई है। विनिर्माण में गजब की तेजी के चलते (2014-15 में 5.5 प्रतिशत की तुलना में 9.5 प्रतिशत) उद्योग में प्रारंभिक तौर पर महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया गया है। इसी बीच, सेवाओं में तेज गति से सुधार होता रहा।

1.30 जहां वास्तविक वृद्धि की गति तेज हो रही है, वहीं सांकेतिक वृद्धि में ऐतिहासिक रूप से कम स्तरों तक

चित्र 4 (क) : जीवीए और स.घ.उ. वृद्धि (प्रतिशत मूल्य)

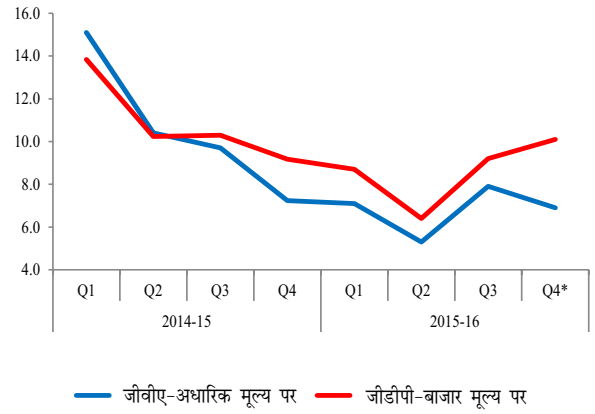

चित्र 4 (ख) : जीवीए और स.घ.उ. वृद्धि (स्थिर मूल्य)

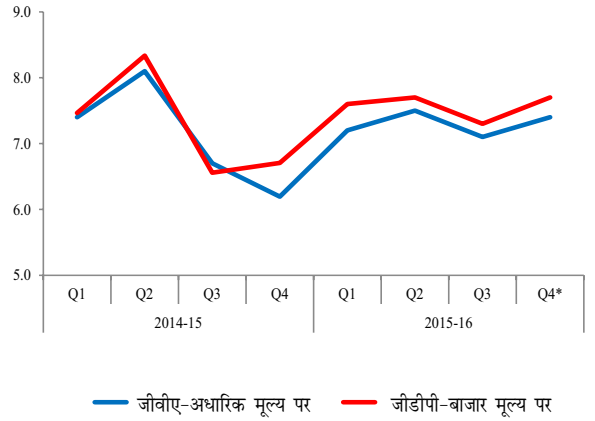

स्रोत: सीएसओ

***चौथी तिमाही में जीवीए वृद्धि का आशय केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2015-16 के अग्रिम अनुमानों और तिमाही अनुमानों से जीवीए की संख्या से है।**

गिरावट आ रही है, एम वाई ई ए में एक असामान्य प्रवृत्ति चिह्नांकित की गई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक जीडीपी (जीवीए) 2015-16 में केवल 8.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सांकेतिक दृष्टि से, निर्माण क्षेत्र स्थिर रहने की आशा है, जबकि व्यापार और वित्त संबंधी गतिशील क्षेत्रों में केवल 7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

1.31 मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही (चित्र-5)। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-नई श्रृंखलाएं मुद्रास्फीति लगभग 5.5 प्रतिशत के आस-पास रही, जबकि अंतर्निहित प्रवृत्तियों, कोर मुद्रास्फीति, ग्रामीण मजदूरी वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि-के उपाय इसी प्रकार से धीमे रहे हैं। इसी दौरान, नवम्बर, 2014 से थोक मूल्य सूचकांक नकारात्मक रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंतरर्राष्ट्रीय वस्तुओं, खासकर तेल, की कीमतों में जबर्दस्त गिरावट हुई। चूंकि मुद्रास्फीति निम्न बनी हुई है और कीमत स्थिरता में भरोसा बढ़ा है, अत: आयात नियंत्रण की अवधि (चित्र-6 में डॉट वाली लाल रेखाएं) के समाप्त होने पर भी स्वर्ण निर्यात काफी हद तक स्थिर रहा है।

1.32 इसी प्रकार, विदेशी स्थिति सुदृढ़ प्रतीत होती है। चालू लेखा घाटे में कमी आई है और यह सुखद

चित्र 5: थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति तथा ग्रामीण मजदूरी वृद्धि (प्रतिशत)

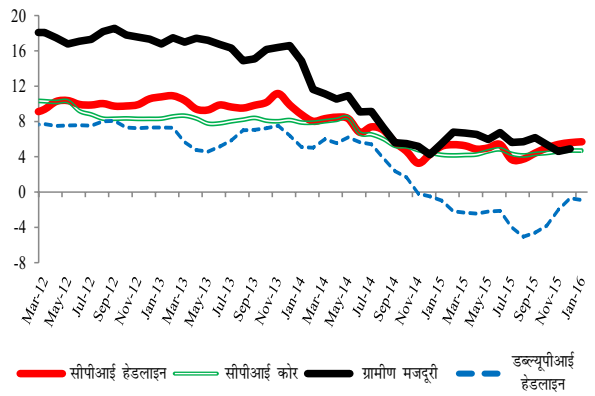

चित्र 6: स्वर्ण आयात टन में (3 एमएमए)

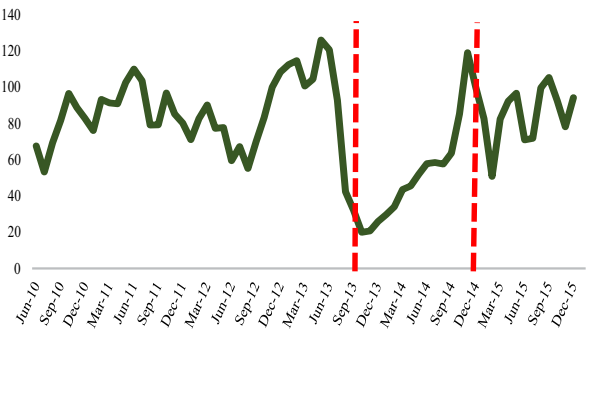

स्रोत: सीएसओ

स्रोत: वित्त मंत्रालय

***चित्र 5 में लंबवत रेखाएं वह अवधि दर्शाती हैं जिससे आगे स्वर्ण आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए (अगस्त 2013 नवंबर 2014)**

स्थिति में है; विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2016 के प्रारंभ में बढ़कर 351.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है तथा आरक्षित मुद्रा भंडार की पर्याप्तता संबंधी मानकों से काफी ऊपर है, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 में 21.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2015-16 की इसी अवधि में बढ़कर 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है; तथा रूपये का सांकेतिक मूल्य, मुद्राओं के समूहों की तुलना में मापित, स्थिर रहा है [(चित्र 7 (क) से (घ)]। परिणामतः भारत दिसम्बर, 2015 में आई मुद्रा नीति को सामान्य बनाने के लिये यू एस फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयों से अस्थिरता से निपटने में अच्छी स्थिति में रहा। यद्यपि डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट आई है, किन्तु यह अपने अन्य व्यापार भागीदारों की मुद्राओं की अपेक्षा सुदृढ़ हुआ है।

1.33 राजकोषीय क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण सफलताएं दर्ज हुईं: अनवरत राजकोषीय समेकन; बेहतर अप्रत्यक्ष कर संग्रहण क्षमता; और सरकार के सभी स्तरों पर खर्च की गुणवत्ता में सुधार।

1.34 बजट पूर्वानुमान के सापेक्ष मामूली सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में कमी (अग्रिम अनुमानों के अनुसार 8.6 प्रतिशत की तुलना में बजट 2015-16 में 11.5 प्रतिशत) के बावजूद, केन्द्रीय सरकार राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुये सकल घरेलू उत्पाद के अपने 3.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य

चित्र 7 क: चालू खाता घाटा (स.घ.उ. का प्रतिशत)

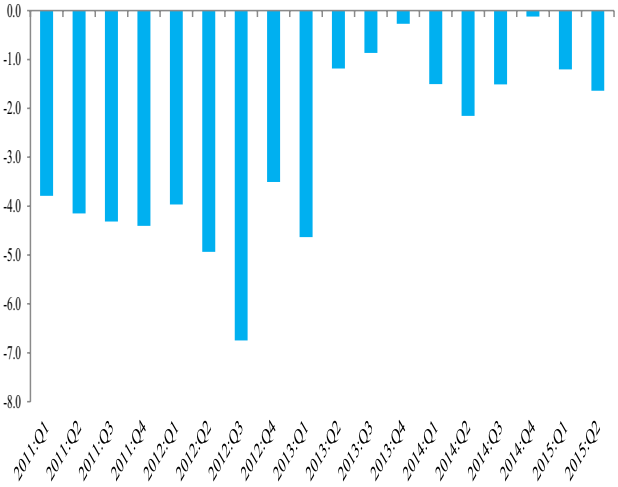

चित्र 7 ख: विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

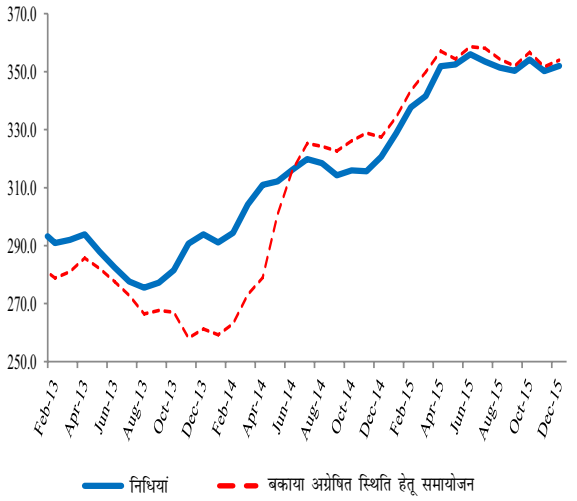

चित्र 7 ग: पूंजी अंतर्वाह के प्रमुख घटकों में प्रवृत्तियां (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

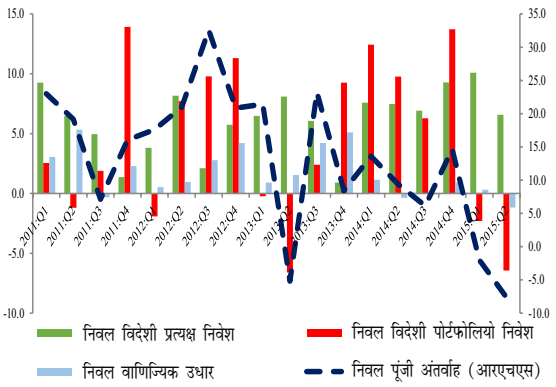

चित्र 7 घ: एनईईआर, आरईईआर और अमेरिकी डॉलर विनिमय दर सूचकांक (2010-100)

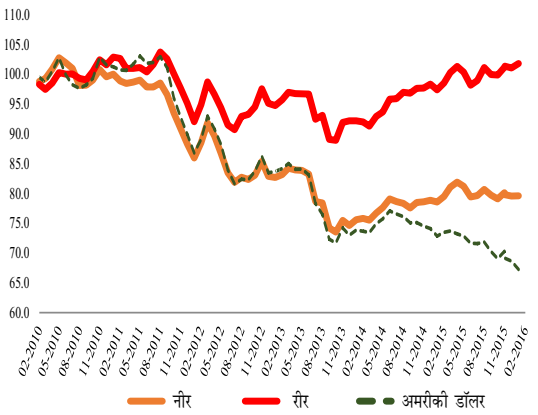

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

को पूरा करेगी। अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुनिश्चितता के बावजूद, राजकोषीय घाटा के 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत से 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.0 प्रतिशत रहने की आशा है। इसके अतिरिक्त, पहले 8 माह में (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) में समेकित राजस्व घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.8 प्रतिशतांक कम हुआ है ।

1.35 सरकार का कर राजस्व बजट में नियत स्तर से अधिक रहने की आशा है। प्रत्यक्ष कर 2015-16 के पहले 9 महीने में 10.7 प्रतिशत बढ़ा। अप्रत्यक्ष कर में भी उछाल रहा। अंशत: इसने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद करों तथा स्वच्छ भारत उपकर में वृद्धि प्रदर्शित की। अप्रैल - सितम्बर 2015-16 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में 90.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह गतवर्ष इसी अवधि में 0.7 लाख करोड़ रूपये की तुलना में 1.3 लाख करोड़ रूपये रहा। कर निष्पादन से कर प्रशासन में सुधार भी प्रदर्शित हुआ क्योंकि अतिरिक्त राजस्व उपायों के न किये जाने के पश्चात् भी राजस्व में वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 10.7 प्रतिशत (बिना अतिरिक्त राजस्व उपायों के) तथा 34.2 प्रतिशत (अतिरिक्त राजस्व उपायों के साथ) की वृद्धि हुई। तालिका-1, गत तीन वर्षों के औसत की तुलना में 2015-16 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कर उछाल, हालांकि अप्रत्यक्ष करों के लिये इससे भी अधिक, में सुधार दर्शाती है।

1.36 राजकोषीय स्थिति के मामले न केवल बृहत आर्थिक परिणामों के लिये हैं बल्कि खर्च की क्षमता के लिये भी हैं। बजट में व्यय को वर्तमान से पूंजीगत व्यय में बदलकर गुणता में सुधार करने पर विचार किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने और राज्यों के बृहद अंतरण और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन से व्यय की गुणता के मुद्दे का सामान्य सरकार (अर्थात् केन्द्र और राज्य) के परिप्रेक्ष्य में आकलन किया जाना जरूरी है। बाक्स 1.3 में इसका ब्यौरेवार वर्णन है।

1.37 मुख्य निष्कर्ष यह है कि खर्च करने की गुणता को राजस्व से निवेश और फिर सामाजिक क्षेत्रों की ओर किये जाने का स्वागत हुआ है। इस वित्तीय वर्ष को आठ महीनों में कुल सरकारी निवेश में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें केन्द्र का (54 प्रतिशत) और राज्यों का 46 प्रतिशत) योगदान रहा है।

संभावनाएं

वास्तविक जीडीपी वृद्धि

1.38 2015-16 के लिये वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 से 7.75 की रेंज में होने का अनुमान है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पहलू के विभिन्न और व्यापक ऑफ सेटिंग घटनाक्रमों को दर्शाती है। तथापि, इन कारकों का विश्लेषण करने से पहले, पीछे जाकर एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान देना जरूरी है।

तालिका-1: कर उछाल

वर्ष	आधार वृद्धि	राजस्व वृद्धि		अंतर्निहित उछाल	
		डीटी	आईडीटी	डीटी	आईडीटी
2012-13	15.1	18.5	25.8	1.2	1.7
2013-14	11.4	13.5	4.1	1.2	0.4
2014-15	12.7	8.2	8.0	0.6	0.6
औसत 2012-15	13.1	13.4	12.6	1.0	1.0
9 माह 2015	8.3	9.2	11.7	1.1	1.4

टिप्पणी:

1. आधार चालू बाजार मूल्यों पर विनिर्माण और सेवाओं में जीवीए का सार है
2. वार्षिक आंकड़े इस वर्ष में चार तिमाहियों का औसत है।

डीटी: प्रत्यक्षकर आईडीटी: उत्पाद कर जमा सेवा कर 9 माह : अप्रैल-दिसम्बर

***स्रोत:* सीएसओ और लेखा महानियंत्रक**

बॉक्स 1.3: वित्त वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार के खर्च करने की गुणता का आकलन

2015-16 के केन्द्रीय बजट में व्यय की गुणता में सुधार करने, संसाधनों को वर्तमान से पूंजीगत व्यय में बदलने और खेती पर विपत्ति के समय कृषि क्षेत्र के लिये अधिक संसाधन देने का उल्लेख किया गया है। साथ ही चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, जिन्हें सरकार ने मान लिया था, में यह निहित है कि राजस्व का अधिकांश हिस्सा राज्यों द्वारा खर्च किया जा सकता है। परिणास्वरूप, केन्द्र की कार्य नीति में बदलाव सफल हुआ है अथवा नहीं, इसे समझने के लिये सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारें) के व्यय का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है न कि केवल केन्द्र सरकार के व्यय का विश्लेषण।

मध्यवर्षीय आर्थिक विश्लेषण (एम वाई ई ए) 2015-16 के लिये किये गये विश्लेषण के क्रम में जिसमें वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही शामिल है, हम इस वित्त वर्ष (एफ वाई 2016) के प्रथम आठ माह के इस विश्लेषण के परिणाम दे रहे हैं। इन परिणामों को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। इनमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं।

प्रथम, सामान्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।1 यह खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशतांक बढ़ा है[2] (चित्र 1) । जिसके विश्लेषण से यह पता चलता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है जिसमें केन्द्र का 54 प्रतिशत और राज्यों का 46 प्रतिशत योगदान है। इस प्रकार, सरकारी निवेश में तेजी लाने की समग्र बजट कार्य नीति अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है ।

चित्र 1 : पहले 8 महीनों में स.घ.उ के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकार का व्यय

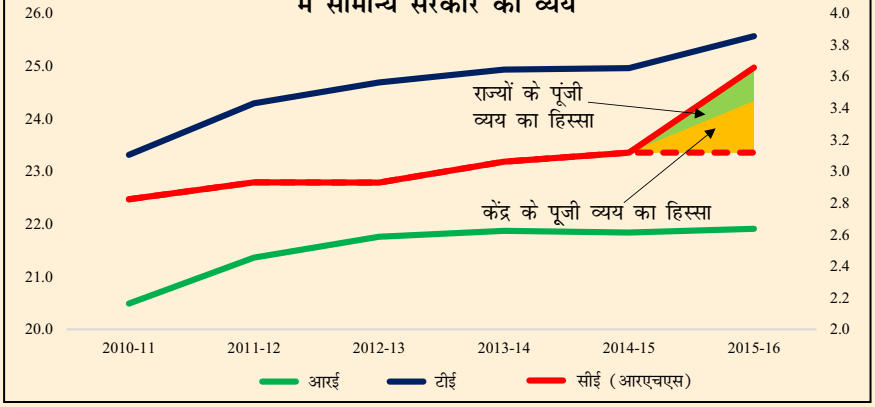

दूसरे, वित्त वर्ष 2016 के प्रथम आठ माह में, सामान्य सरकार के व्यय में जी डी पी के हिस्से के रूप में और वास्तविक अर्थों में, तीन मुख्य क्षेत्रों - शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तथा ग्रामीण विकास में वृद्धि देखी गयी है। उदाहरण के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तथा ग्रामीण विकास में वास्तविक व्यय में क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।3 उपलब्ध डाटा में इन विकास कार्यों के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों के योगदान को पुनः पृथक नहीं किया गया है।

चित्र 2 : पहले 8 महीनों में सामान्य सरकारी व्यय (स.घ.उ का प्रतिशत)

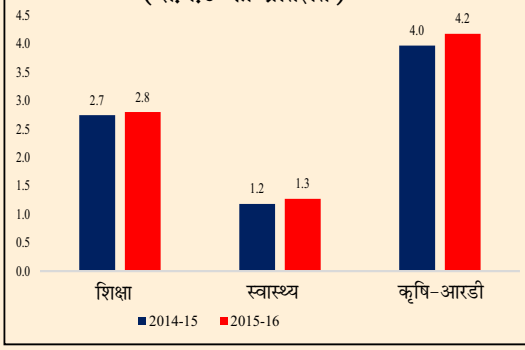

चित्र 3 : पहले 8 महीनों (2015-16) में वास्तविक व्यय-वृद्धि

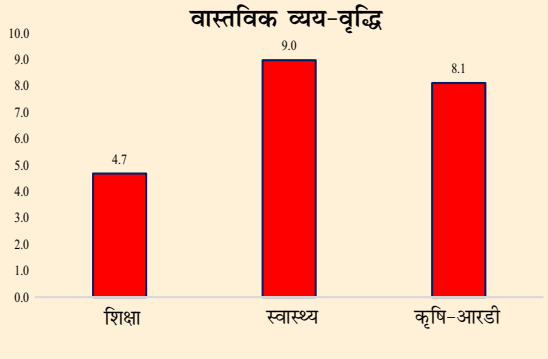

स्रोत: **लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक, सीएसओ और परिकलन**

1 केन्द्र सरकार के पूंजीगत व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल हैं जबकि डाटा उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया गया है।

2 सरलता के लिये पूर्ण वर्ष की जीडीपी को पूरे वर्ष में बराबर बांटा गया है।

3 स्वास्थ्य व्यय और कृषि तथा ग्रामीण विकास पर हुए व्यय संगत सीपीआई सूचकांक के द्वारा अपस्फीत हो गए हैं।

1.39 भारत की दीर्घावधि तक चलने वाली संभावित जीडीपी वृद्धि पर्याप्त है, संभवत: 8-10 प्रतिशत (बॉक्स 1.1) है। लेकिन अल्पावधि में इसकी वास्तविक वृद्धि, वैश्विक वृद्धि और मांग पर भी निर्भर करेगी। कुल मिलाकर, विनिर्मित माल और सेवाओं का भारत का निर्यात जीडीपी का लगभग 18 प्रतिशत है जो एक दशक पहले के लगभग 11 प्रतिशत से अधिक है।

1.40 वैश्वीकरण में भारत की बढ़ती हुयी हिस्सेदारी को दर्शाते हुये भारत की विकास दर और विश्व की विकास दर के बीच सह-संबंध तेजी से बढ़कर उपयुक्त उच्च स्तर तक पहुंच गया है। 1991-2002 की अवधि के लिये यह सह-संबंध 0.2 था। तब से अब तक यह दुगुना होकर 0.42 (चित्र-1) हो गया है। दूसरे शब्दों में, विश्व की विकास दर में 1 प्रतिशतांक की गिरावट का सीधा संबंध भारत की विकास दर में 0.4 प्रतिशतांक की गिरावट से है।

1.41 तदनुसार, यदि विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर रहती है, तो भारत के विकास में अत्यधिक बाधाएं आयेंगी। उदाहरणार्थ, यदि विश्व की विकास दर में वर्ष 2003-11 के दौरान दर्ज 4-4.5 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त करने की बजाय, अगले कुछ वर्षों में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि जारी रहती है तो भारत की मध्यावधि विकास दर 8-10 प्रतिशत तक बढ़ने की दीर्घकालीन संभावना की बजाए 7-7.5 प्रतिशत के निकट रहने की संभावना है, सरकार के सुधारक प्रयासों के बावजूद। दूसरे शब्दों में, वर्तमान वैश्विक परिवेश में विकास की संभावनाओं और परिणामस्वरूप मूल्यांकन के मानकों को पुन: नियत करना जरूरी होगा।

1.42 2016-17 की संभावनाएं देखते हुये, हमें कुल मांग: निर्यात, उपभोग, निजी निवेश, और सरकार के प्रत्येक घटक की जांच करना जरूरी है।

1.43 भारत की निर्यात की मांग का अनुमान लगाने के लिये, हम भारत के निर्यात के भागीदारों की प्रतिनिधि भारित औसत जीडीपी वृद्धि दर का परिकलन करेंगे। ये भार भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में भागीदार देशों का हिस्सा हैं। हमने देखा कि निर्यात की मांग में वृद्धि के लिये यह प्रोक्सी 2014 में 3.0 प्रतिशत से गिरकर 2015 में 2.7 प्रतिशत रह गई जिससे भारत की तेल से इतर निर्यात की वस्तुओं में कमी को स्पष्ट करने में मदद मिलती है, यद्यपि मंदी की गंभीरता दरअसल निर्यात मात्र में ह्रास-प्रतिकूल विदेशी घटनाक्रम से परे चली गयी (चित्र-8)। आई एम एफ के वर्तमान अनुमान यह दर्शाते हैं कि व्यापार भागीदार में वृद्धि से इस मांग में इस वर्ष लगभग 2.8 प्रतिशत मामूली सुधार होगा। किन्तु पर्याप्त डाउन साइड जोखिमों से यह पता चला है कि निर्यात निष्पादन में सुधार से जी डी पी वृद्धि में बहुत बड़े योगदान पर भरोसा न करना विवेकपूर्ण होगा।

1.44 घरेलू मोर्चे पर, दो कारक खपत को बढ़ा सकते हैं। यदि और जिस सीमा तक सातवें वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग) को लागू किया जाता है, तो सरकारी

चित्र 8: कुल निर्यातों, वाणिज्यिक सेवा निर्यातों और तेल-भिन्न निर्यातों एवं तेल-भिन्न निर्यात मात्रा के मूल्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)

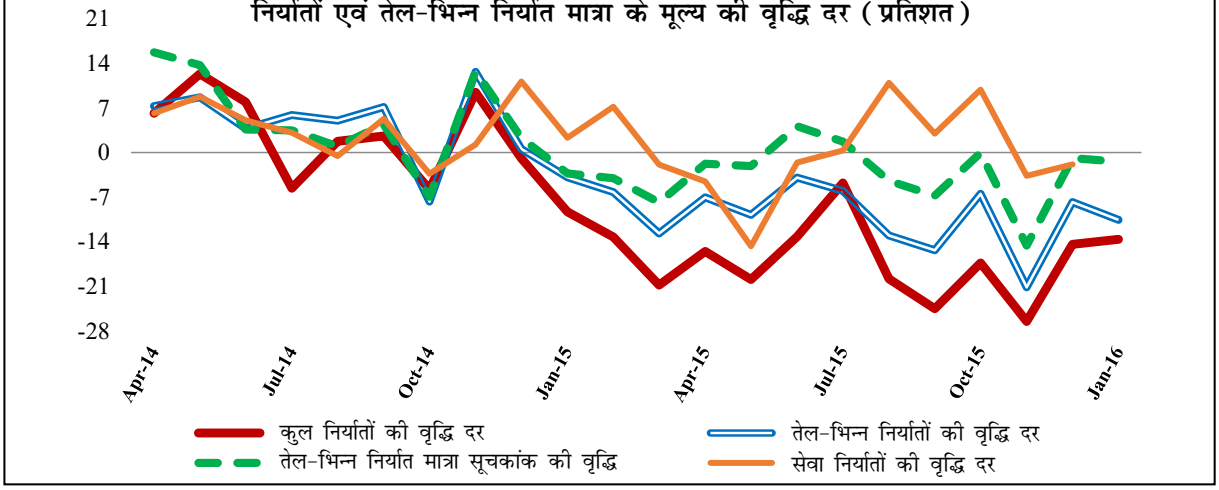

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

कर्मचारियों के उच्चतर वेतन और भत्तों के अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय करना शुरू होगा। इसके साथ ही, यदि मानसून सामान्य होता है तो कृषि आय में सुधार (बॉक्स-1.5 देखें) होगा। जिसके साथ ग्रामीण खपत के लिये लाभ बढ़ेगें जो पिछले दो वर्षों में कमजोर बारिश के कारण कम रहा है।

1.45 इसके विपरीत, पिछले वर्ष के तेल की कीमतों से अप्रत्याशित लाभ के समाप्त होने से खपत में वृद्धि कम होगी। वर्तमान संभावनाओं से यह पता चलता है कि तेल की कीमतें (भारतीय अशोधित मात्रा) 2015-16 में प्रति बैरल 45 अमेरिकी डॉलर की तुलना में अगले वित्त वर्ष में औसतन प्रति बैरल 35 अमेरिकी डॉलर हो सकती हैं। परिणास्वरूप आय से लाभ जीडीपी के लगभग एक प्रतिशतांक के बराबर होगा जिससे कीमत में 18 प्रतिशत की गिरावट से निवल तेल आयात का हिस्सा 6 प्रतिशत हिस्सा जीडीपी में बैठता है। किन्तु यह पिछले वर्ष के लाभ का आधा होगा, इस प्रकार इससे अगले वर्ष खपत में वृद्धि कम होगी।

1.46 वस्तुत: कंपनी क्षेत्र के लाभ के लिये क्रेडिट स्यूस (गैर वित्तीय) द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार कारपोरेट क्षेत्र की लाभदायकता इस वर्ष दिसंबर 2015 तक में एक प्रतिशत घटकर कमजोर रही है। इस ह्रास से धातुओं-प्रधानत: इस्पात संबंधी कंपनियों की वित्तीय स्थिति में तीव्र पतन दृष्ट हुआ। ऐसी कंपनियां गंभीर वित्तीय तंगी वाली कंपनियों की स्थिति में अब पड़ गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक तंगी वाली कंपनियों, जिनकी आय ब्याज देनदारियां चुकाने में नाकाफी हैं, द्वारा लिए गए निगमित ऋण का हिस्सा दिसंबर 2014[3] में 35 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर दिसंबर 2015 में 41 प्रतिशत तक हो गया है। इस स्थिति के कारण, कंपनियां पूंजीगत व्यय में पर्याप्त कटौती करने पर पुन: विवश हो गयी हैं।

1.47 अंतत: वित्तीय समेकन का मार्ग सरकार की घरेलू आउट पुट की मांग निर्धारित करेगा। मांग और आउट पुट पर ड्रैग की मात्रा, लगभग 1 के गुणांक को मानते हुये, समेकन की राशि के बराबर होगी।

1.48 यहां तीन महत्वपूर्ण डाउन साइड जोखिम हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल से निर्यात के लिये आउटलुक बदतर हो सकता है और वित्तीय दशाएं पर्याप्त रूप से तंग हो सकती हैं। दूसरा, यदि अनुमान के विपरीत, तेल कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे प्रत्यक्ष रूप से और मौद्रिक सुविधा की संभावनाओं में कमी के कारण खपत की बाधा में वृद्धि होगी। अंतत: सबसे बड़ा गंभीर जोखिम उपर्युक्त दोनों कारकों का सम्मिलित होना है। ऐसा तब हो सकता है जब तेल बाजार पर आपूर्ति संबंधी कारकों जैसे प्रधान उत्पादकों द्वारा उत्पादन प्रतिबंधित करने के करार का दबदबा हो जाए।

1.49 एक महत्वपूर्ण बेहतर संभावना अच्छे मानसून की है, इससे ग्रामीण खपत में उस सीमा तक वृद्धि होगी कि मूल्य का दबाव कम हो जाएगा, मौद्रिक सुविधा के लिये और अवसर खुलेंगे। (बॉक्स 1.6)

1.50 इन कारकों को एक साथ लेते हुये, हम विश्व की अर्थव्यवस्था में चल रहे घटनाक्रम के कारण कम जोखिमों के साथ इस जीडीपी में वास्तविक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान करते हैं। व्यापक स्तर के पूर्वानुमान में इस समय कृषि में उछलन से पूर्ण अंतरराष्ट्रीय संकट तक, बहिर्जात घटनाक्रमों की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। यह ऐसी अनिश्चितता को भी दर्शाता है जो आर्थिक कारोबार के सामान्य और वास्तविक जमा राशियों में वृद्धि के बीच अंतर को दर्शाता है।

---

[2] जैसा कि ईबीआइटीडीए से मापित है, नकदी प्रवाह लाभ का सामान्य निर्धारण; यह ब्याज, कर, मूल्य ह्रास और ऋण चुकौती से पूर्व की आय से संकलित है।

[3] एक से कम ब्याज कवर अनुपात का अर्थ है कि निगम वित्तीय परेशानी में हैं क्योंकि इसकी आय इसकी ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है। अनुसंधान यह दर्शातें हैं कि बडी कंपनियों के लिये 2.5 गुणा से कम और छोटी कंपनियों के लिये 4 गुणा से कम का ब्याज कवर निवेश ग्रेड से नीचे माना जाता है।

बॉक्स 1.4: स्टार्ट-अप और गतिवाद

अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र जिसमें अवसामान्य गति दिखाई पड़ रही है, स्टार्ट-अप क्षेत्र है, और यह ई-वाणिज्य तथा वित्तीय सेवाओं पर जोर दे रहा है। जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, भारत में 19,400 तकनीकी समर्थित स्टार्ट-अप थे, जिनमें से पांच हजार 2015 में ही प्रारंभ कर चुके थे[1]। कम से कम 2000 स्टार्ट-अप की सहायता उद्यम पूंजी/ऐंजल निवेशक द्वारा 2010 से की गई है। इनमें से 1005 का उद्भव 2015 में ही हो गया था। भारतीय स्टार्ट-अप ने 2015 के पूर्वार्ध में निधियन में 3.5 बिलियन डॉलर जुटाया और भारत में सक्रिय निवेशकों की संख्या 2014 में 220 से बढ़कर 2015 में 490 हो गई[2]। दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार 8 भारतीय स्टार्ट-अप 'यूनिकॉर्न' क्लब (मूल्यन 1 बिलियन डॉलर से अधिक है) से संबंधित थे।

यह महत्वपूर्ण बात है कि स्टार्ट-अप भी 'एक्जिट' (अध्याय 2 का मुख्य अंश) से जुड़ें हैं, जो इससे सूचीबद्ध की जा रही इन कंपनियों का रूप लेगा। इससे मूल निजी निवेशकों को प्रारंभिक निवेश से लाभ उठाने की अनुमति होगी और इसे अन्य समान उद्यमों में निवेश किया जा सकेगा। भारत में एक्जिट मूल्यन अभी भी कम है परंतु इनके बढ़ने की संभावना है क्योंकि सूचीयन पर सेबी की नई नीतियों का प्रभाव पड़ेगा और इक्विटी बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था में निराशा की भावना से उत्पन्न वर्तमान अल्प मूल्यन से सामान्य रूप से सशक्त होगा।

---

[1] योर स्टोरी एंड आईएसपीआईआरटी द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित

[2] एनएएसएससीओएम प्रतिवेदन का शीर्षक 'स्टार्ट-अप इंडिया- मूमेंट्स राइज ऑफ इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम'।

बॉक्स 1.5: एल नीनो, ला नीना और वित्त वर्ष 2017 के लिये कृषि पूर्वानुमान

समय समय पर एल नीनो से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, इक्वेडोर और पेरू के निकट प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गरम होने से पूरे विश्व में मौसम पैटर्न असामान्य हुआ है। 1997, से अब तक वर्ष 2015 का एल नीनो सबसे अधिक प्रभावी रहा है, जिससे पिछले वर्ष उत्पादन कम हुआ। लेकिन यदि इसके बाद प्रभावी लॉ नीना आता है तो 2016-17 में बहुत अच्छी फसल हो सकती है।

1997 का यह दौर लगभग अप्रैल, 1997 से जून, 1998 तक जारी रहा। इन 15 महीनों के दौरान ओशनिक नीनो इंडेक्स (ओ एन आई) - जो पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर की सतह के तापमानों की उनके दीर्घावधिक औसत से तुलना प्रस्तुत करता है तथा जिसका इस्तेमाल करके यू एस नेशनल ओशनिक एंड एटमोसफिरिक एडमिनिसट्रेशन (एन ओ ए ए) एल नीनो घटनाओं का पता लगाता है - लगातार सकारात्मक तथा 0.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा ।

वर्तमान एल नीनो फरवरी 2015 में शुरू हुआ था; अधिकांश जलवायु मॉडलों के पूर्वानुमान के अनुसार मई, 2016 से पहले सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी। इसके चलते इसकी अवधि 1997-98 की घटना जितनी लंबी हो जाएगी। तीव्रता की दृष्टि से भी इसकी तुलना 1997 की घटना से की जा सकती है: नवंबर-2015 - जनवरी 2016 के लिए हालिया ओ एन आई 2.3 डिग्री सेल्सियस ही था जो 1997-98 की इसी अवधि के स्तर जैसा था।

हालांकि यहां अभी आशा बनी हुई है। एन ओ ए ए डाटा के अनुसार, 1950 से अब तक भिन्न -भिन्न अवधि और तीव्रता के 22 एल नीनो आ चुके हैं। किन्तु इस एक एल नीनो से पहले के 21 एल नीनो के बाद ला नीना आया था जिससे दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ-साथ समुद्र की सतह में पानी असामान्य रूप से ठंडा हो गया और ओ एन आई -0.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। 1950 से 14 बार ऐसे एल नीनो आये हैं जिनमें भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। यह घटना वायुमंडलीय संवहन गतिविधि का परिणाम हो सकता है, अब इसका स्थान आस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है।

अब एक अच्छी बात यह है कि कुछ मजबूत एल नीनो (वर्ष 1997-98, 1972-73, 2009-10, 1986-87 और 1987-88 तीव्रता का क्रम है और इसमें अंतिम चार में भारत में सूखा पड़ा था) के बाद ला नीनो आया, जिससे फसल बहुत अच्छी हुई। रिकार्ड के अनुसार 2016 में भी दूसरा मजबूत एल नीनो आने के बाद पुन: इसी स्थिति के बनने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नीचे चित्र यह दर्शाता है कि ला नीना के वर्षों में भारत में कृषि की औसत वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी जो इस अवधि की औसत से काफी अधिक थी।

चित्र : कृषि वृद्धि, 1981-82 से 2015-16 (औसत, प्रतिशत)

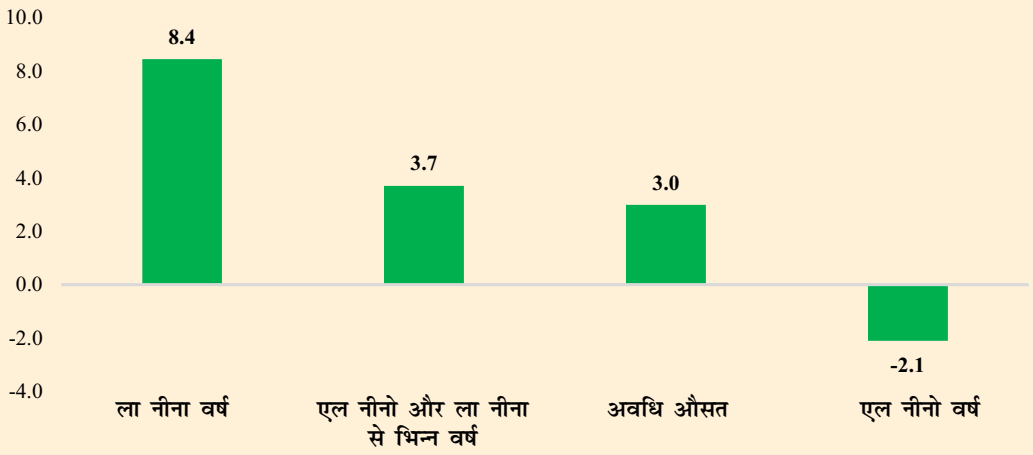

एल नीनो वर्ष (बहुत प्रचंड, साधारण)
1982-83, 1986-87, 1987-88, 1991-92, 1997-98, 2002-03, 2009-10, 2015-16

ला नीना वर्ष (बहुत प्रचंड, साधारण)
1988-89, 1998-99, 1999-00, 2007-08, 2010-11

लेकिन एक समस्या यह है कि एल नीनो अभी भी मजबूत स्थिति में है और यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। यह ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही सामान्य स्थिति में प्रवेश करेगा। एन ओ ए ए के नवीनतम पूर्वानुमान अनुसार, जून-जुलाई में ला नीना की केवल 22 प्रतिशत उम्मीद है जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार वर्ष की दूसरी छमाही में इसके सामान्य स्थिति में आने और उसके बाद ला नीना के आने की सर्वाधिक संभावना है।

दूसरे शब्दों में, दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितम्बर) की दूसरी छमाही से पहले ला नीना की स्थिति बनने की आशा नहीं की जानी चाहिये। फिर भी, यदि यह आता है तो इसके फलस्वरूप भारत में वास्तविक वर्षा होने में समय लग सकता है। कुल मिलाकर 2015 के एल नीनो का प्रभाव केवल जुलाई से देखा गया था जबकि पूर्वी मध्य प्रशांत समुद्र की सतह का तापमान फरवरी से बदलना शुरू हो गया था।

इन सबका निष्कर्ष यह है कि आने वाले मानसून में अथवा कम से कम खरीफ के मौसम के अंत तक, ला नीना के अपने पूर्ण प्रभाव से आने की संभावना नहीं है। तथापि, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि खराब मानसून आयेगा, विशेषरूप से जब सभी प्रतिदर्श यह बता रहे हैं कि इस वर्ष एल नीनो के दुबारा घटने की संभावना बहुत कम है। मानसून ''पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल'' जैसे अन्य अनुकूल कारकों से अच्छा भी हो सकता है। बाद वाली घटना जहां अफ्रीका के निकट पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय हिन्द महासागर का पानी दक्षिण इंडोनेशिया के पूर्व में महासागर के पानी से अधिक गरम हो गया - ने कम से कम दो एल नीनो वर्षों (1997 और 2006) को रोका था, परिणामस्वरूप भारत में सूखा नहीं पड़ा था।

ऐसे स्पष्ट पूर्वानुमान की नीतिगत समस्या यह है कि सरकार को मानसून के लिये आकस्मिक योजना तैयार रखनी चाहिये विशेषकर लगातार दो वर्षों तक सूखा पड़ने के बाद। खरीफ की बुआई से काफी पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके किसानों को घरेलू आपूर्ति के दबावों (जैसे दालें) की संभावना वाली फसलों का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करना और संवेदी वस्तुओं के आयात का समय पर ठेका देना इस कार्यनीति के अनिवार्य घटक होंगे।

बॉक्स 1.6: दोहरे तुलनपत्र की चुनौती का सामना करना

भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर रहीं अधिकांश गंभीर अल्पकालिक चुनौतियों में से एक चुनौती दोहरे तुलनपत्र (टीबीएस) की समस्या – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और कुछ बृहत कारपोरेट घरानों की अनर्जक वित्तीय स्थितियां हैं। इन्हें हमने अब तक ''भारतीय विशेषताओं के साथ तुलनपत्र संलक्षण'' के रूप में वर्णित किया है। अब यह बात साफ है कि टीबीएस समस्या निजी निवेश और इसके बाद पूर्ण विकसित आर्थिक समुत्थान के लिए प्रमुख व्यवधान है।

बैंकिंग व्यवस्था की समस्याएं कुछ दिनों से बढ़ रही हैं। प्रतिबलित आस्तियों (अनर्जक ऋण पुनर्गठित और आस्तियों) में 2010 से बढ़ोतरी होती रही है जिससे पूंजीगत परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ रहा है, यहां तक कि बाज़ेल-3 की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। बैंकों ने पूंजी संरक्षण के उद्देश्यों से स्थावर अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह सीमित करके उपाय किए हैं, जबकि निवेशकों ने विगत वर्षों में बैंक मूल्यनों को घटाकर उपाय किए हैं। अनेक बैंकों के शेयर उनके अंकित मूल्य से कम पर अच्छा परिणाम दे रहे हैं।

कुछ मामलों में, तुलनपत्र की यह सुभेद्यता कारपोरेट क्षेत्र, विशेष रूप से उन बड़े व्यावसायिक घरानों, जिन्होंने अवसंरचना और वस्तुक संबंधी व्यवसायों जैसे कि इस्पात में निवेश करने हेतु व्यावसायिक तेजी के वर्षों में भारी भरकम उधार लिया। समान कमजोरियों का प्रतिबिंबित करता है, कारपोरेट के लाभ तो कम हैं जबकि बढ़ते ऋणों से कंपनियां नकदी प्रवाह को संरक्षित करने हेतु निवेश को कम करने हेतु बाध्य हो रही हैं।

यह हालात बनाए नहीं रखे जा सकते; एक निर्णायक समाधान आवश्यक है। परंतु समाधान पाना कठिन है। शुरू में परस्पर संबंधित समस्याओं को देखते हुए समाधानों के माध्यम से तुलनपत्रों के दोनों सेटों में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। विगत वर्ष के अगस्त में, सरकार ने इन्द्रधनुष योजना शुरू की जिसमें बैंक के पुन:पूंजीकरण हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम शामिल है। इस बीच, आरबीआई ने 5:25 और एसडीआर योजनाएं प्रारंभ कीं, जो बैंकों के लिए प्रोत्साहन सृजित करते हैं ताकि वे प्रतिबलित आस्तियों को कार्यक्षम बनाने के लिए उनसे उधार लेने वालों की मदद कर सकें। परंतु ये तो आरंभिक उपाय हैं जिनसे व्यापक समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

टीबीएस चुनौती का समाधान करने के लिए ये उपाय हैं : मान्यता, पुन: पूंजीकरण, समाधान और सुधार। बैंकों को अपनी आस्तियों का मूल्य निर्धारण वास्तविक मूल्य (मान्यता) के लगभग करना चाहिए, जैसाकि आरबीआई बार-बार जोर देकर कहता रहा है; जैसे ही बैंक ऐसा करते हैं उनके पूंजीगत हालात इक्विटी, (पुन: पूंजीकरण) में वृद्धि, जैसाकि बैंक मांगते रहे हैं, के जरिए सुरक्षित होंगे; निगमित क्षेत्र की विचाराधीन प्रतिबलित आस्तियां बेच दी जाएंगी या कार्यक्षम बना दी जाएंगी जैसाकि सरकार इच्छा करती रही है; और निजी क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र के आगामी प्रोत्साहनों को दुरूस्त (सुधार) करके समस्या को दुबारा न होने दिया जाए, जैसाकि प्रत्येक की मांग रही है।

परंतु इन उपायों का निर्धारित अनुक्रम में होना जरूरी है। मान्यता को पहले रखना होगा, परंतु इसके साथ-साथ संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति करनी होगी; अन्यथा बैंक सुभेद्य हो जाएंगे। मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीएसबी के पुन: पूंजीकरण हेतु संसाधन कहां से आएंगे?

एक संभावित स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र का निजी तुलनपत्र है। उदाहरणार्थ, सरकार उन आस्तियों को बेच सकती है जिसे वह धारित करने की इच्छुक नहीं हो; जैसे कि कतिपय गैर-वित्तीय कंपनियां; और पीएसबी में अतिरिक्त निवेश करने के लिए इससे हुई आय का इस्तेमाल कर सकती है। यह विकल्प तार्किक रूप से बोधगम्य है। जिस बात पर कम ध्यान दिया जाता है, वह यह है कि आरबीआई ऐसा कर सकता है। अर्थात् यह अपनी पूंजी को काम में पुन: लगा सकता है।

सभी वित्तीय फर्मों की भांति, केन्द्रीय बैंक ऐसी पूंजी रखते हैं कि जो जोखिम वह लेते हैं उसके लिए पूंजी उपलब्ध हो सके। केन्द्रीय बैंकों के मामले में, जोखिम उत्पन्न होने का कारण है कि घरेलू मुद्रा की दृष्टि से विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य विनिमय दर के साथ-साथ घटता बढ़ता है; जबकि सरकारी प्रतिभूति, का मूल्य जो बैंक के स्वामित्व में रहती है, ब्याज दर की घट-बढ़ से बदलता रहता है। इन जोखिमों का आकलन और यह आकलन करना कठिन है कि कितनी पूंजी इन जोखिमों के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए। इसी कारण से केन्द्रीय बैंक की पूंजी धारिता में व्यापक रूप से भिन्नता होती है।

चित्र : मुख्य केंद्रिय बैंकों के तुलनपत्र के प्रतिशत के रूप में कुल इक्विटी
(पूंजी, धारित अर्जन और आकस्मिकता)

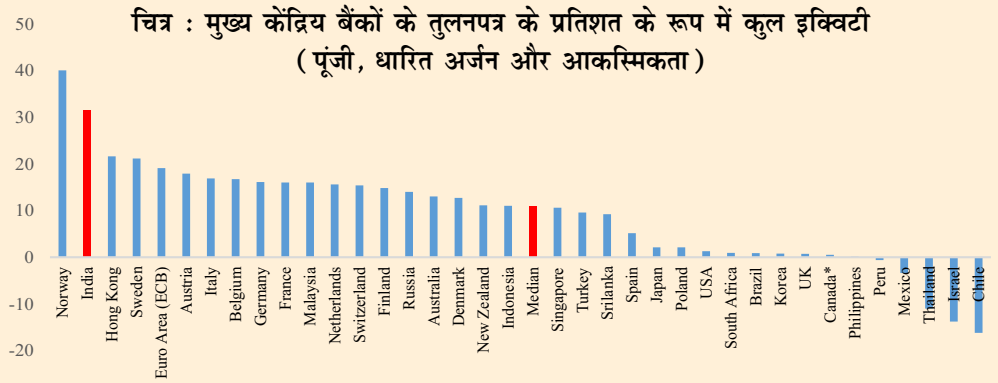

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

उपर्युक्त चित्र में विभिन्न केन्द्रीय बैंकों की आस्तियों में शेयरधारक इक्विटी का अनुपात दर्शाया गया है। शेयरधारक इक्विटी की जो परिभाषा है उसमें पूंजी आरक्षित निधि (अवितरित प्रतिधारित आय से निर्मित) + पुनः मूल्य निर्धारण और आकस्मिक व्यय खाता शामिल है। यह चार्ट दिखाता है कि आरबीआई लगभग 32 प्रतिशत के इक्विटी शेयर के साथ ऊपर के चित्र में दृष्टि पूंजी में बाहरी तत्व है और यूएस फेडरल रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंग्लैंड जिनका अनुपात 2 प्रतिशत से कम है, से काफी ऊपर है। दि कंजर्वेटिव यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और कुछ ईएम सेंट्रल बैंक का अनुपात बहुत उच्च है, परंतु वे भी आरबीआई के स्तर को नहीं छू पाते।

यदि आरबीआई नमूने (16 प्रतिशत) के माध्यिका तक पहुंच भी जाए तो इससे पूंजी की पर्याप्त रकम उपलब्ध होगी जिसे पीएसबी के पुनः पूंजीकरण के काम में लगाया जा सकता है।

निःसंदेह, ध्यान में रखे जाने के लिए आवश्यक विचार व्यापक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई कदम सरकार और आरबीआई के बीच संयुक्त और सहयोगी रूप से उठाने की जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि पूंजी के पुनः इस्तेमाल से आरबीआई की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और वित्तीय सुस्थित सुरक्षित रहेगी और ऐसा होते हुए दिखाई भी देगी। इस दशा में महत्वपूर्ण है व्यापक मुद्दा कि जो पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र के तुलन पत्र में पहले से विद्यमान है, उसका पुनः आबंटन करके पुनःपूंजीकरण के लिए निधि, कुछ हद तक, प्राप्त की जा सकती है।

मान्यता के समर्थक संसाधन चिह्नित हो जाने पर शेष दो उपाय (समाधान और सुधार) पर जोर से काम किया जा सकता है। यहां अनेक विकल्प भी हैं जिनमें चारों उपायों को कार्यान्वित करने वाले ''बैड बैंक'' का सृजन शामिल है।

मुद्रास्फीति

1.51 चालू वित्त वर्ष के अधिकांश समय में, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहकर आरबीआई की लक्षित सीमा 4-6 प्रतिशत के अंदर गतिशील रही। किन्तु जो निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है, वह है सातवें वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मियों के लिए अनुशंसित पारिश्रमिक और लाभ में बढ़ोतरी। यदि सरकार यह सिफारिश मंजूर कर लेती है तो क्या इससे मूल्यों एवं मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान अस्थिर होंगे। अधिक संभावन यही है कि ऐसा नहीं होगा।

1.52 ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात पर स्पष्ट हैं। चित्र 9 में छठे वेतन आयोग का अनुभव दिखाया गया है। यह सितम्बर, 2008-सितम्बर, 2009 तक धनराशि देने की अवधि के दौरान, गैर खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में वेतन में हुई मासिक बढ़त दिखाता है। (उस समय समग्र मुद्रास्फीति वैश्विक खाद्य मूल्य में तीव्र बढ़ोतरी के कारण बढ़ रही थी।) यह चित्र दर्शाता है कि बकाया प्रदान करने के कारण छठे वेतन आयोग के पंचाट ने मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव दर्ज नहीं किया। यदि छठे वेतन आयोग ने मुद्रास्फीति को नाम मात्र प्रभावित

चित्र 9 : छठे वेतन आयोग के बाद गैर-खाद्य मुद्रास्फीति और वेतन बिल में वृद्धि (प्रतिशत)

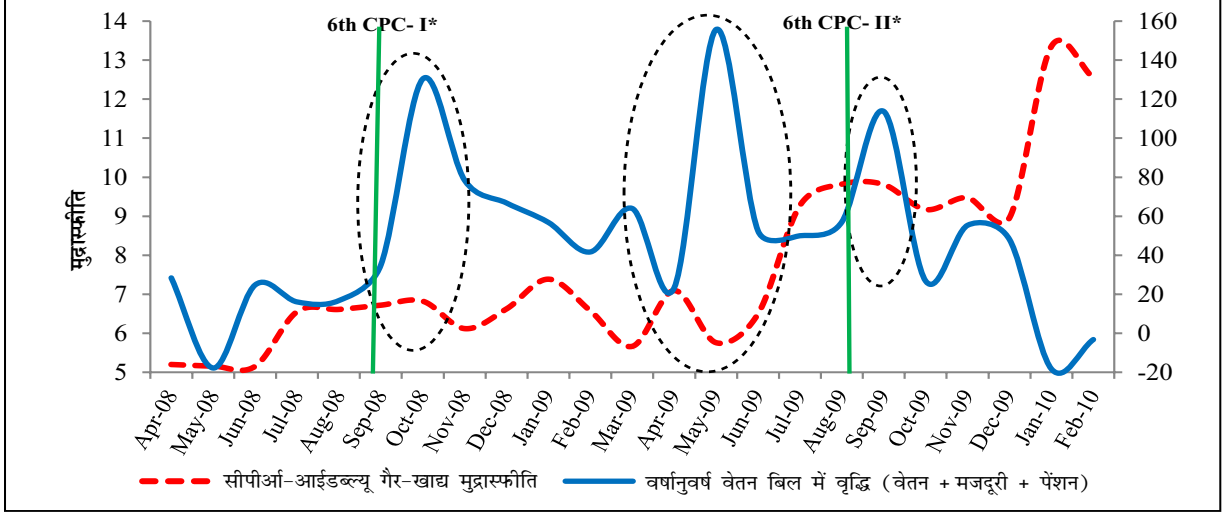

स्रोत: **सीएसओ, छठा वेतन आयोग रिपोर्ट, बजट दस्तावेज और सीजीए**

* **छठे पीसी के चरणबद्ध कार्यान्वयन को प्रतिबिम्बित करते हुए उदग्र रेखा से बकाया भुगतान का समय संकेतित होता है।**

किया, तो 7वें पीसी से यह भी नहीं होगा, संबंधित राशि के परिमाण को देखते हुए; पूरी तरह लागू किए जाने के बावजूद, प्रत्याशित मजदूरी बिल छठे पीसी में 70 प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा सातवें पीसी में लगभग 52 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

1.53 यह निष्कर्ष आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है। *मजदूरी में बृहत वृद्धि से मुद्रास्फीति पर नगण्य प्रभाव क्यों पड़ता है।* इसके तीन कारण हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण व्यापक सैद्धांतिक तथ्य है। सिद्धांत रूप में, मुद्रास्फीति वह अंश संकेतित करती है जिसके कारण सकल मांग सकल आपूर्ति से अधिक हो जाती है और वेतन भुगतानों से सकल मांग का एक लघु भाग ही पूरा होता है। दरअसल इनसे सरकारी मांग पूरी नहीं होती। यह समग्र वित्तीय घाटा पर निर्भर करती है जो देश द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय किए जाने की राशि और करों द्वारा वापस लिए जाने वाली धनराशि का अंतर होता है। चूंकि सरकार वित्तीय घाटा कम करने पर प्रतिबद्ध रहती है। अत: मजदूरी बढ़ने के बावजूद मूल्यों पर दबाव घटेगा।

1.54 उक्त सिद्धांत से जान पड़ता है कि सार्वजनिक क्षेत्रक मजदूरी में तीव्र बढ़त से मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है, यदि यह निजी क्षेत्रक मजदूरी में और निजी क्षेत्रक मांग में व्याप्त हो जाए। परंतु फिलवक्त यह प्रक्रिया सुस्त है, क्योंकि निजी क्षेत्रक श्रम बाजार में पर्याप्त शिथिलता है जो ग्रामीण मजदूरी (चित्र 4 देखें) के ह्रास में दृष्ट है और यदि निजी क्षेत्रक मजदूरी फिर भी बढ़ती है तो न्यून उपयोग (चित्र 10) में पर्याप्त अतिशय क्षमता के होने से जान पड़ता है कि लागत वृद्धि को उपभोक्तो मूल्यों पर सरकाना फर्मों के लिए मुश्किल प्रतीत हो सकता है।

1.55 अंततोगत्वा, सीपीआई के आवास घटक पर मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि का कुछ प्रक्रियागत प्रभाव होगा। किन्तु यह प्रभाव लगभग 0.15 से 0.3 प्रतिशतता के मामूली अंकों'' के रूप में हो सकता है और तब भी यह सीपीआई के स्तर पर न कि वर्धमान मुद्रास्फीति दर पर जो आरबीआई का वास्तविक लक्ष्य है, वन ऑफ प्रभाव मात्र होगा।

1.56 मुद्रास्फीति संबंधित विचार अन्य कारकों पर बाद में निर्भर करता है। घरेलू पक्ष में, अल्प संभाव्य वृद्धि के दूसरे वर्ष का अर्थ यह होगा कि उत्पादन अंतराल (मसलन ह्रासमान क्षमता उपयोग में प्रतिबिम्बित) और व्यापक होगा। इसके फलत: अंतर्हित मुद्रास्फीति पर जो तेल संबंधित उप सूचकाकों (चित्र 11) को छोड़कर सेवा मुद्रास्फीति से मापित 5 प्रतिशत से नीचे पहले ही गिर गई, है अतिरिक्त अधोमुखी दबाव होगा। इस बीच यदि मानसून सामान्य समय

चित्र 10 : क्षमता उपयोग

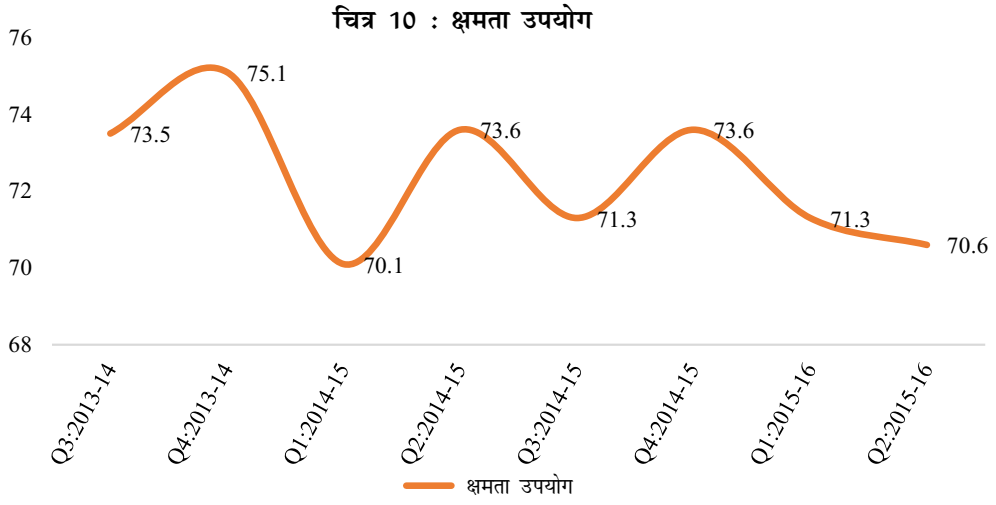

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

4 समग्र सीपीआई में किराए वाले सरकारी मकान का भार 0.35 प्रतिशत है। परंतु इसमें केंद्र और राज्य सरकारें तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। चूंकि केवल केंद्र सरकार के आवान भत्ते दिए जाते हैं, अत: सीपीआई पर प्रभाव और भी मामूली हो जाएगा।

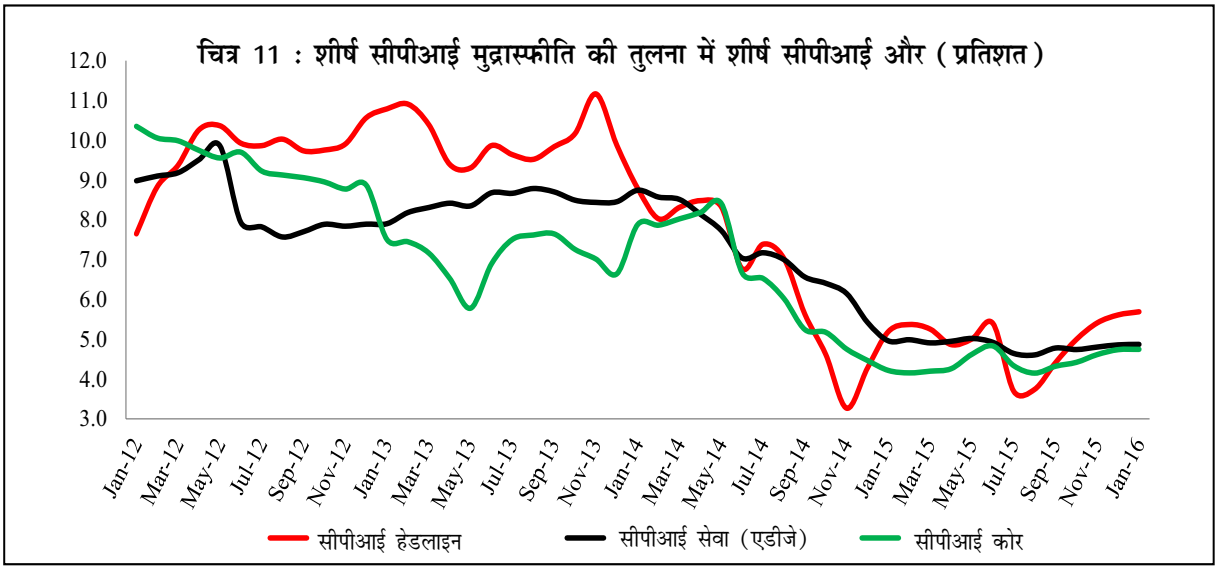

स्रोत: **सीएसओ,**

पर दस्तक दे देता है तो खाद्य कीमतें अकष्टकर हो जाएंगी, खासकर चूंकि सरकार अन्नों से संबंधित एम एस पी में नियंत्रित वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहती है, और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि मंद रहती है।

1.57 बाहर से और अधिक राहत मिलनी चाहिए। 2016 के प्रथम दो महीनें में तेल मूल्य के साथ वस्तु मूल्य में बढ़ोतरी होना बतलाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में इनपुट कीमत कम होने की संभावना है। इस कारक के अतिरिक्त अन्य अपस्फीतिकारी ताकतें भी हैं। चूंकि चीन में लगातार विकास कम हो रहा है, अत: अत्यधिक क्षमता में लगातार वृद्धि हो सकती है जिससे कि पूरे विश्व में व्यापार योग्य वस्तुओं के मूल्यों पर गिरावट का दबाव पडता है। रुपये में गिरावट से उपरी दबाव पड़ता है, विशेषरूप से अगर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज की दरों को लगातार बढ़ाते रहने से यू. एस. में पूंजी वापस आयेगी। इसके बावजूद घरेलू दबाव के साथ आयातित दबावों के जोखिम का संतुलन दृढ़तापूर्वक नीचे के तरफ होता है।

1.58 ये सभी चीजें बतलाती हैं कि मार्च, 2017 तक आर.बी.आई. 5 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वस्तुत: वर्तमान परिदृश्य में लक्ष्य से नीचे रहने का अधिक जोखिम प्रतीत होता है। हालांकि वर्तमान नीतिदर तटस्थ प्रतीत होती है क्योंकि यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से केवल थोड़ी उच्च है, तथापि ग्राहकों को पेश वास्तविक बैंक दरों से नीति दर में होने वाली हाल की गिरावट के पास थ्रू को रोकते हुए नकदी स्थिति असामान्य रूप से कड़क है। (बॉक्स-1.7 देखें)

1.59 चित्र 12 स्थिति को दर्शाता है। खराब मौद्रिक स्थितियों को दर्शाता है: बैंक ऋणदान (आधार) दर और नाममात्र जी डी पी विकास के मध्य अंतर। अगर अंतर नकारात्मक होता है तो नाममात्र जी वी ए विकास औसत फर्म राजस्व विकास के लिये इसके ऋण पर प्रोद्भूत हो रहे ब्याज से तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस दृष्टि से मौद्रिक परिदृश्य में कार्पोरेट क्षेत्र के लिये थोडी समस्याएं सामने आई हैं। परन्तु नाममात्र जी डी पी विकास से ब्याज दर के उच्च होने पर फर्मों के नकद प्रवाह में कमी आ जाती है। अगर फर्म मूल्य बढ़ोतरी की कमी करने पर उपाय करता है तो बिक्री मात्रा और नकद प्रवाह में बढ़ावा मिलता है जिससे मुद्रास्फीति पर अधोमुखी दबाव पड़ता है। यह चार्ट दर्शाता है कि वास्तव में इस वर्ष व्यापक रूप में क्या हुआ है।

[5] बेशक बैंक की ऋण दरें फर्म के तुलन-पत्र की दुर्बलता से भी प्रभावित होती है जिससे उनको कर्ज उपलब्ध कराने का जोखिम बढ़ जाता है।

1.60 इन सभी कारणों से अनुमान किया जाता है कि 2016-17 में सी पी आई की मृदु मुद्रास्फीति साढ़े चार-पांच प्रतिशत के मध्य होगी। इस प्रकार यह समझा जाता है कि आर्थिक नीति के प्रभावी परिदृश्य को दो तरीकों से शिथिल किया जा सकता है। प्रथम, नकदी शर्तों को सरल बनाते हुये चालू नीति दर के साथ अनुरूप बनाया जा सके (बाक्स 1.7)। दूसरा, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुकुल नीति दर में कमी करते हुये दुर्बल आर्थिक क्रियाकलाप और कार्पोरेट तुलन-पत्र का समर्थन करना। वास्तविक जी डी पी में मजबूत वृद्धि से मौद्रिक स्थिति को सरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अधिक विश्वसनीय नकदी योग पर ध्यान देने के साथ जोखिम कार्यनीति उपयोगी है। अगर मुख्य संख्या के परामर्श से वास्तविक वृद्धि कमजोर है तो सरल बनाना उपयुक्त है। दूसरी तरफ वास्तविक जी डी पी वृद्धि वस्तुत: मजबूत है तो आसान किये जाने वाले स्फीतिकारी जोखिमों को कम अंतर्निहित अवस्फीति व्यापक है।

चित्र 12 : तंगी की मौद्रिक स्थितियाँ - बेस रेट और मामूली जीवीए में वृद्धि[6] (प्रतिशत)

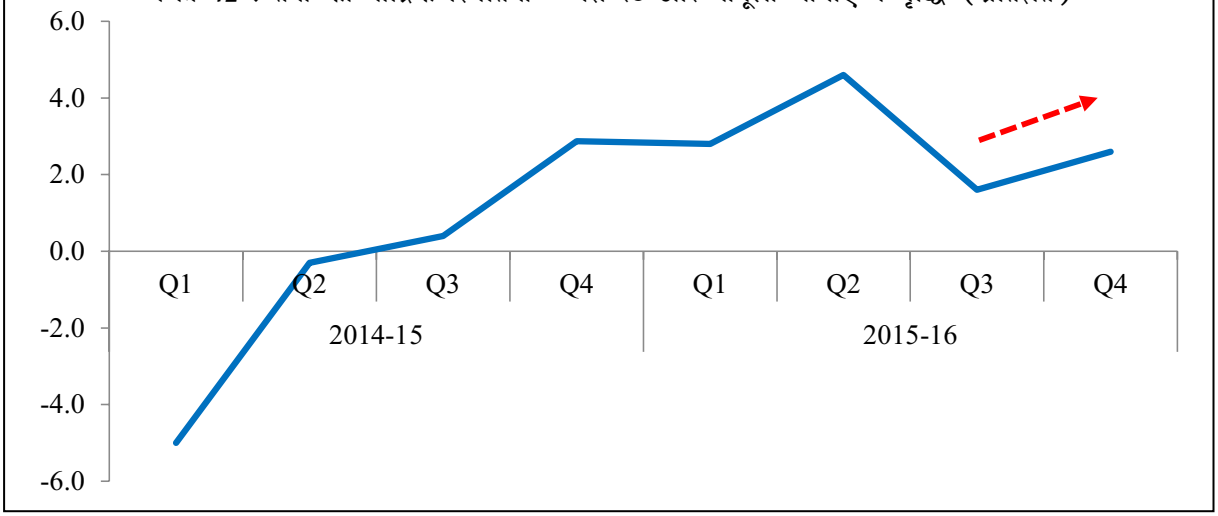

स्रोत: सीएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक

बॉक्स-1.7: मौद्रिक नीति के अपूर्ण पास थ्रू को कैसे स्पष्ट किया जाए ?

फरवरी, 2016 के नीति विवरण के अनुसार आर0बी0आई0 का समंजनशील नीतिगत रवैया अपनाने की ओर चला गया है। बिना संदेह, नीति दरों में पर्याप्त रूप से कमी की गई है: 2015 में दर में चार बार कटौती से कम नहीं हुई तथा इसका योग 125 आधार अंक है जिसमें अक्टूबर की बैठक में 50 आधार अंक की कटौती शामिल हुई है। परन्तु बैंक के कर्ज दरों में समायोजन अधिक निम्न है जो लगभग 50 आधार अंक कम हुई है। नीति दरों से बैंक दरों में पासथ्रू की विफलता को कैसे उचित ठहराया जाए ?

चित्र संचरण समस्या को दिखाता है। यह दर्शाता है कि विगत वर्ष में नीति दरों और बैंक दरों के मध्य अंतर उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा है। जैसे प्रथम दर कटौती से पहले की जमा दरें नीति दर से 50 आधार अंक अधिक थी, जबकि अब 75 आधार अंक के आस-पास अधिक हैं। कर्ज दर में इस बीच 200 आधार अंकों से 275 आधार अंकों तक वृद्धि हुई है।

बहुत से व्याख्याकर्ताओं ने जोर दिया है कि संचरण उच्च प्रबंधित और लघु बचत दरों से सीमित होता है। यह तर्क दिया जाता है कि बैंक इससे चिंतित रहते हैं कि अगर जमा दरों में कटौती की गई तो उपभोक्ता लघु बचत लिखत की तरफ रूख करेगें। यह समझते हुये सरकार लघु बचत योजनाओं की समीक्षा कर रही है ताकि बाजार स्थिति के अनुरूप अनुकुल बनाया जा सके। परन्तु चार्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि छोटी बचत योजनाओं से पासथ्रू हमेशा बाधित नहीं होता। जैसा कि जून में हुये दर कटौती के बाद जमा दरों में बड़ी गिरावट हुई जबकि अक्टूबर की कटौती बहुत अधिक थी जो कि शायद ही सबके पास पहुंचे। और लघु बचत योजनाएँ यह स्पष्ट नहीं कर सकती कि जमा दरों में घटित कटौतियों से उधार दर में अनुरूप गिरावट क्यों नहीं हुई।

परिणामत: ऐसा लगता है कि अतिरिक्त घटक अपना योगदान दे रहे हैं। नकदी की स्थितियों में परिवर्तन एक संभावित घटक हो सकता है क्योंकि इससे नीतिगत दरें पुन: प्रबलित हो सकती हैं या परिवर्तन व्यर्थ हो सकता है। इसका कारण प्रत्यक्ष है : यदि नकदी की स्थितियाँ

[6] त्रैमासिक के लिये बेस दर जनवरी, 2016 का बेस रेट होगा।

चित्र 1 : रेपो दर* आधार दर और सावधि जमा दर में उतार-चढाव

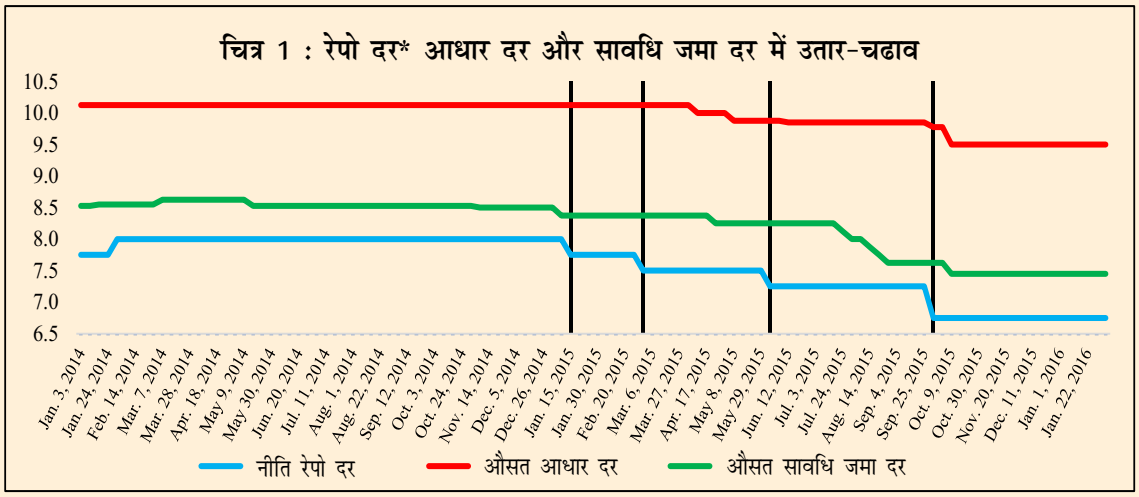

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

*** इन सभी बॉक्स की सीधी रेखाएं रेपो दर में परिवर्तन की घोषणा होने की तारीखों को दर्शाती है।**

खराब हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को खोने के भय से कम जमा दरों की नीतिगत दरों में कटौती करने के संदर्भ में अधिक सतर्क रहना होगा और इसके फलस्वरूप नकदी की अधिकता होगी।

चित्र 2 मात्राओं के संदर्भ में कड़ी मौद्रिक स्थितियों का परिमापन तथा बैंकों की नकदी की मांग के प्रत्युत्तर में रातभर की तथा मियादी रेपो दर (दि 'एलएएफ') के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की धनराशियों के प्रावधान का आलेखन दर्शाते हैं। जून माह की दर कटौती के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक दृष्टिकोण को सुगम बनाए रखने की कार्यनीति के अनुरूप एलएएफ के अंतर्गत बैंकों के ऋण औसतन शून्य हो गए हैं। परन्तु अक्टूबर माह की कटौती के समय कुछ परिवर्तन आ गए : अचानक बैंकों ने पुन: ऋण लेना प्रारंभ कर दिया तथा उनकी मांग औसतन 1 लाख करोड़ रूपये प्रतिदिन से बढ़कर फरवरी, 2016 तक 1.75 लाख करोड़ रूपये प्रतिदिन हो गई।

चित्र 3 और 4 यह दर्शाते हैं कि नकदी की स्थिति खराब मूल्यों में किस प्रकार से दर्शाई गई है अर्थात् बाजार की अल्पकालीन ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक की नीति से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। दरों में प्रथम तीन कटौतियों के पश्चात की अवधि में 91 दिन की टी-बिल दर एवं पुन: खरीद दरों के बीच विस्तार में कमी आई। परन्तु अगस्त से लेकर तेजी से बढ़ी है और अक्तूबर में कटौती के बाद बढ़ोतरी जारी है। (चित्र 3) इसी प्रकार से, दरों में प्रथम तीन कटौतियों के पश्चात की अवधि में मांग मुद्रा दर रेपो दर से कम थी जो कि नकदी की स्थिति अच्छे होने के संकेत थे। अक्तूबर में दरों में कटौती के पश्चात अच्छी स्थितियाँ लुप्त हो गई जोकि नकदी के खराब होने के संकेत थे। (चित्र 4)

चित्र 2 : तंगी की मौद्रिक स्थितियाँ

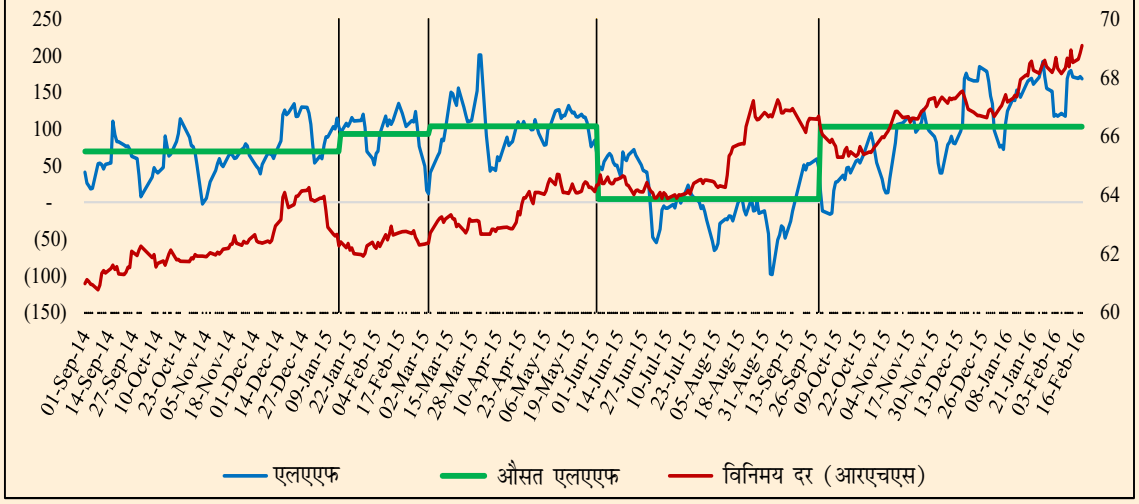

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

जारी....

चित्र 3 : 91-दिवसीय टी-बिल एवं रूपये/डॉलर की विनिमय दरों के विस्तार का उच्चावचन

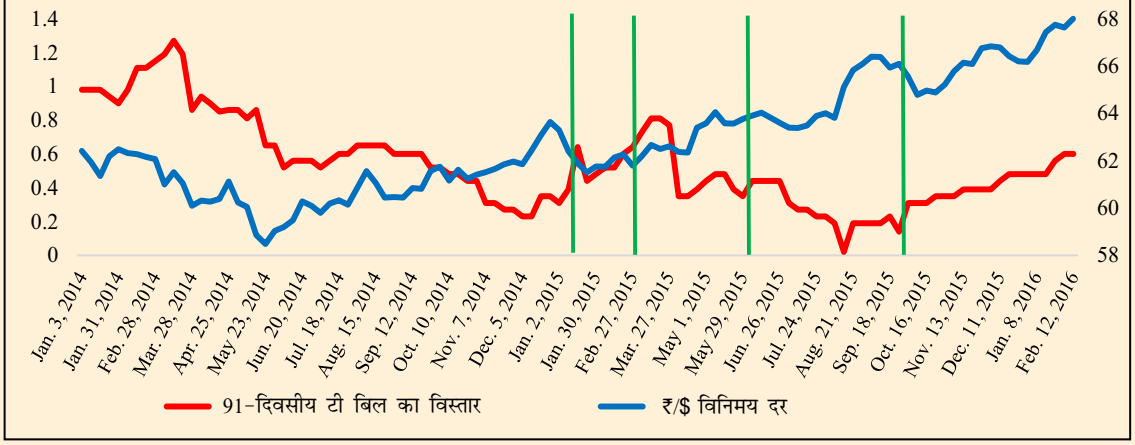

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मात्रा एवं मूल्य संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2015 के अंतिम महीनों के प्रारंभ में नीतिगत दरों में कटौती के बावजूद चलनिधि की स्थिति खराब थी। इसका परिणाम यह हुआ कि घरेलू विकास तथा अत्यधिक ऋणग्रस्त कारपोरेट क्षेत्र का विकास और स्थिति को छोड़कर बाजार की ब्याज दरें एवं विनिमय दरें हैं।

चित्र 4 : मांग मुद्रा दर और पालिसी रेपो दर की प्रवृत्तियाँ

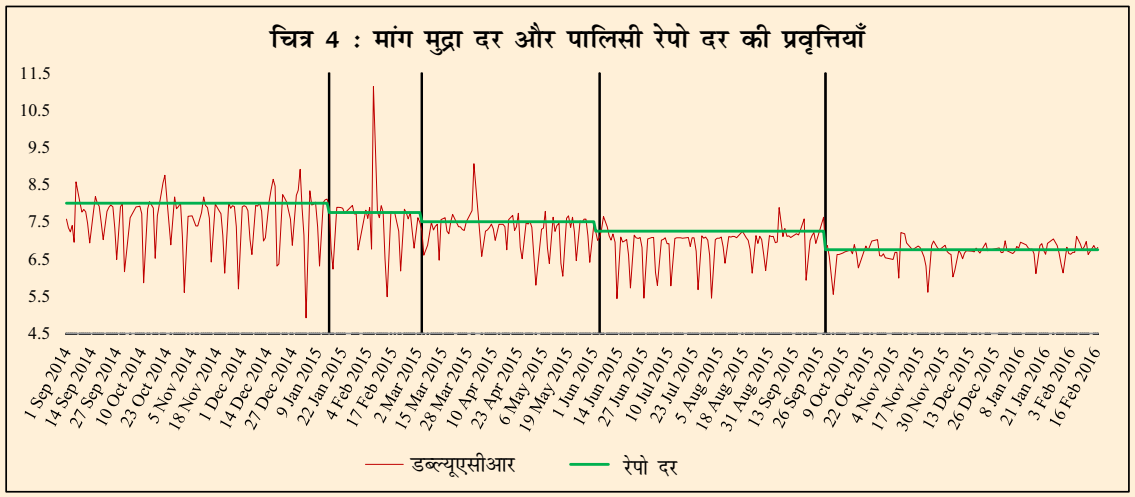

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मध्यावधि राजकोषीय रूप रेखा

1.61 वर्ष 2016-17 के राजकोषीय झुकाव का आकलन दो संदर्भों में किए जाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से, इसका आकलन संवृद्धि एवं मुद्रास्फीति के संभावित अल्पकालीन दृष्टिकोण के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इस पर मध्यावधि संदर्भ में भी विचार किया जाना अपेक्षित है। यह इसीलिए कि बजट नीति का सर्वाधिक मूलभूत कार्य राजकोषीय संपोषणीयता का संरक्षण करना है। सरकार को मौजूदा समय में लिए गए ऋणों का पुर्नभुगतान कल करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में होना चाहिए। इस स्थिति को सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

1.62 सरकारें लक्ष्य हासिल करने के लिए तथा राजकोषीय संपोषणीयता के संकेतों के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों में समष्टि घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा तथा स.घ.उ. अनुपात

[7] Reinhart, C.,K. Rogoff, and M.A. Savastano, 2003, "Debt Intolerance", NBER Working paper No. 9908

के लिए ऋण शामिल है। सिद्धांतत: सतत अनुपात समय, देश एवं ऐतिहासिक घटकों (रिइनहर्ट, रोगोफ एवं सवास्तानो, 2003) के अनुरूप हैं। परन्तु इन आकस्मिकताओं एवं लक्ष्यों के बीच संबंध स्थापित करना वैज्ञानिक रूप से कठिन है। तदनुसार, प्राय: देश अन्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई देश राजकोषीय घाटे के लिए जीडीपी के 3 प्रतिशत के लक्ष्य को और जीडीपी अनुपात के ऋण के लिए 60 प्रतिशत के लक्ष्य को केवल इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि इन लक्ष्यों को यूरोप द्वारा स्थिरता एवं संवृद्धि विकास (एसजीपी) के संदर्भ में अपनाया गया था।

1.63 यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार संपोषणीयता के पथ पर अग्रसर है जोकि इसके सघउ अनुपात के ऋण की दिशा है। यदि यह अनुपात कम हो रहा है तो सरकार की आधारभूत राजकोषीय सुदृढ़ता में सुधार हो रहा है। वर्ष 2008-2009 से लेकर अब तक की अधिकांश अवधि में विश्व व्यापी वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान, हालांकि, भारत सरकार के ऋण के अनुपात में सुधार नहीं हुआ है। प्रारंभ में, वृहत्तर वार्षिक घाटा सबसे बड़ी बाधा थी, जिसको सरकार द्वारा इसको अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में देखा गया था। अंततोगत्वा इन घाटों को कम कर दिया गया था परन्तु फिर भी समग्र रूप से इन असंतुलनों को बढ़ने नहीं दिया गया जोकि वर्ष 2013-14 तक एक दूसरी बाधा थी: विनिमय दर में अत्यधिक गिरावट से विदेशी ऋण के रूपये मूल्य में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी।

1.64 परिणामस्वरूप ऋण अनुपात को समेकित सरकार (केन्द्र एवं राज्य) के जी डी पी 67 प्रति0 के आस-पास रखते हुये, सरकारी ऋण में जी डी पी के वृद्वि की तीव्रता के अनुरूप ही वृद्धि हुई है। उभरते हुये एशिया के कई बड़े देशों की तुलना में यह अनुपात उच्च है, भारत की क्रेडिट रेटिंग इनसे मेल खाती है। तदनुसार, सरकार जी एफ सी उपरांत प्रवृति को तोड़ने एवं ऋण अनुपात को नीचे की ओर बेहतर अनुकुल स्तरों पर बनाये रखने के लिये संकल्पित है।

1.65 इस कारण से, जैसा कि पिछले बजट में परिकल्पित था उसी के अनुरूप आक्रामक वित्तीय समेकन के मार्ग के पक्ष में मजबूत तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इस प्रकार का निम्न घाटा न केवल ऋण संचय को कम करेगा बल्कि कुछ व्यापक लाभ भी उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले, इसका तात्पर्य यह होगा कि सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, जिससे इसकी विश्वनीयता में वृद्धि होगी, जो कि कमान करने वाले किसी भी प्राधिकरण की सबसे महत्वपूर्ण आस्तियां हैं। विलोमत:, यह समझ से परे है कि ऐसी प्रतिबद्धताओं का क्यों त्याग किया जाए, जब अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हो रही है ऐसी तीव्र वृद्धि से उम्मीद है कि यह बजट के लिये पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराएगी, जबकि सरकारी मांग में कमी को आसानी से सहन करने में अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाएगी। इस प्रकार, विश्वसनीयता एवं मितव्ययिता के लिये जीडीपी लक्ष्य के 3.5 प्रतिशत तक का अनुपालन अपेक्षित है।

1.66 तथापि, बहस इसके दूसरे पक्ष पर भी है। व्यवहार्यता की दृष्टि से, दो कारकों के कारण वर्ष 2016-17 एवं इसके आगे के राजकोषीय कार्य जटिल हो गये हैं:

- सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी वेतन एवं भत्ते पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाएं। इस वेतन पारितोषिक का पूर्ण कार्यान्वयन, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, केन्द्र के मजदूरी बिल के लिये जीडीपी में लगभग 1/2 प्रतिशत की वृद्धि करेगा ।
- अवसंरचना आवश्यकताओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिये सार्वजनिक निवेश में और अधिक वृद्धि किये जाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी वृद्धि खर्च को 2010/11 के स्तर पर जीडीपी के लगभग 2 प्रतिशत पर वापस ला देगी, जो कि अन्य उभरते हुये बाजारों से बेहद नीचे होगी ।

1.67 इन कारकों के मद्देनजर, केन्द्र का घाटा पर्याप्त रुप से बढ़ सकता है। परिणामस्वरूप, मूल लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होगा जब तक कर वृद्धि खर्चों में कटौती न किया जाए। इसे पूरा करने के लिए निवेश और स्पेक्ट्रम से प्राप्तियों के बढ़ने की गुंजाइश है जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता होगी।

1.68 दूसरे, यहां तक कि आक्रमक राजकोषीय

समेकनों की रणनिति की वांछनीयता पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा माहौल जोखिम से भरा हुआ है, जो जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, भारत के विकास के सभी मुख्य इंजनों के लिए खतरा है। परिणामत: राजकोषीय मांग को पर्याप्त रूप से घटाने और अपनी उगाही को तीव्र करने के बजाए सरकार के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि वह इस जोखिम को कम करने के लिए बीमा खरीदे। बीमा की खरीद की आवश्यकता को डाटा अनिश्चितता बल देती है।

1.69 लेकिन, यदि घाटा लक्ष्य में छूट प्रदान की जाती ही तो, दो प्रश्नों के जबाव अपेक्षित होंगे। पहला, ब्याज दर का क्या होगा? राजस्व घाटे जितने कम होंगे उधारी आवश्यकताएं उतनी ही कम होंगी और संभवत: सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर कम होगी जो कि उन कंपनियों के लिये बहुत लाभकारी होगी जो अपनी ऋण देनदारियों को पूरा कर पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तथापि, अंतरर्राष्ट्रीय आनुभाविक अनुसंधान से पता चलता है कि दीर्घावधि दरों पर मुद्रास्फीतियों के प्रभाव आमतौर पर छोटे और अनिश्चित होते है। इसका धीमा कारण यह है कि: मूलरूप से दीर्घावधि दरों का निर्धारण अल्पावधि दरों के भविष्य के रूख के प्रति उम्मीदों पर आधारित होते हैं और यह उम्मीद पथ आमतौर पर मुख्यत: वृद्धि और मुद्रास्फीति के प्रति दीर्घावधि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, न कि अपरिहार्य रूप से मौजूदा वर्ष के बजट घाटा पर।

1.70 भारत के मामले में, दीर्घावधि दरों पर बजट घाटे का प्रभाव किसी अन्य जगह की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि अधिकांश सरकारी प्रतिभूतियां (जी. सेक) बैंकों द्वारा धारित हैं और बैंकों की बॉण्ड आपूर्तियों को आत्मसात करने की क्षमता सीमित है। यह जोखिम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों की बड़ी हिस्सेदारी (होल्डिंग) जमा कर ली है जो कि सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) के तहत धारित किये जाने वाले आवश्यक न्यूनतम मात्रा की तुलना में बहुत बड़ी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले कुछ वर्षों में राज्य बॉण्डों की महत्वपूर्ण मात्रा अर्जित होगी क्योंकि विद्युत वितरण कंपनियों को दिये गये बैंक ऋण उदय योजना के तहत प्रतिभूत होते हैं। इसलिये बैंकों की अतिरिक्त बॉण्ड इश्यू की आवश्यकताएं सीमित प्रतीत होती हैं।

1.71 वस्तुत: अतिपूर्ति के जोखिम बिल्कुल अल्प प्रतीत हो रहे हैं। शुरूआत में, जी डी पी के 3.5 प्रतिशत से थोड़ी अधिक होने पर भी राजस्व घाटा में कटौती का तात्पर्य है – जीडीपी से जुड़े निम्न निवल बॉण्ड इश्यू और बैंक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद के प्रति वस्तुत: उत्सुक हो सकते हैं क्योंकि गिरते हुये तेल मूल्यों के कारण मुद्रास्फीति कम होगी, जिससे ब्याज दर कम होंगे और बैंक अपनी हिस्सेदारियों पर पूंजी लाभ प्राप्त करेंगे। इसी समय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी अपनी खरीददारी में वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूति निवेशों की सीमाओं में छूट प्रदान करती रही है। विलोमत: यदि विदेशी मुद्रा प्रवाह कम रहता है तो स्वयं आर बी आई को सरकारी प्रतिभूतियां खरीदनी पड़ सकती हैं ताकि पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सके। अंतत: यदि मांग कमजोर पड़ती है तो सरकार अपने पर्याप्त नकदी शेष को रोकने के बजाय हमेशा ही अपने बॉण्ड इश्यू का दुबारा आकलन कर सकती है ।

1.72 अल्पावधि ब्याज दरों का क्या करें? ऐसी कोई जोखिम तो नहीं है कि बड़े पे अवार्ड के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी जो आर बी आई को अपने नीतिगत दर में वृद्धि के लिये विवश करेगी? जैसा कि उपर चर्चा की गई है, ऐसे जोखिम बहुत कम ही हैं क्योंकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि या यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि होती है। वस्तुत: निम्नलिखित कारणों से मुद्रास्फीति के अधिक पर्याप्त जोखिमों में कमी आएगी: निम्न तेल मूल्यों से, धीमी होती चीनी अर्थव्यवस्था और बड़े हुये मांग पर किसी आकार के राजकोषीय घाटा कटौती का प्रभाव।

1.73 चक्रीय प्रतिफल के संग्रहण, राजकोषीय समायोजन की डिग्री में छोटे अंतर का ब्याज दरों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसका अर्थ है कि निम्न ब्याज दरों से होने वाले बड़े समायोजन (मितव्ययता)का सकारात्मक प्रभाव कुल मांग पर सीधे नकारात्मक प्रभाव के रूप में पड़ता है। इसी तरह, समायोजन की छोटी

मात्रा वस्तुत: वृद्धि (विकास) में सहायक सिद्ध होगी।

1.74 अभी भी एक दूसरा मुद्दा छूटा हुआ है: ऋण को नीचे की ओर उन्मुख करने की आवश्यकता है। यह जानना कि क्या यह समायोजन की अधिक संयत गति से संभव हो पाएगी, मध्यावधि राजकोषीय दृष्टिकोण का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना उचित है। सरकारी ऋण के बुनियादी ड्राइव (उद्देश्य) को संक्षेप में विहित किया जा सकता है। विनिमय दर, जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, की गतिशिलता के अलावा, ऋण से जीडीपी अनुपात का उत्थान दो कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक निम्नलिखित हैं: (i) प्राथमिक घाटे का स्तर, अर्थात्, राजकोषीय घाटा जब ब्याज लागत को इससे अलग कर दिया जाए, एवं (ii) सरकारी ऋण पर ब्याज दर और न्यूनतम जीडीपी की वृद्धि (पूर्व वर्ष के ऋण अनुपात द्वारा गुणित) के बीच अंतर जैसे:

$$d(t)- d(t-1) = p_d(t) + [i-g]/[1+g]*d(t-1)^{8}$$

1.75 सीधे शब्दों में कहें तो, प्राथमिक घाटा ऋण अनुपात को बढ़ावा देता है। लेकिन, सांकेतिक विकास इसे नीचे ला सकता है,जब तक कि विकास दर सरकारी ऋण पर ब्याज दर से अधिक नहीं हो जाती है। प्राथमिक घाटा को 2011-12 में दर्ज जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत से बहुत नीचे, 2015-16 में जीडीपी के एक प्रतिशत से कम पर नियंत्रित रखा गया। लेकिन सांकेतिक विकास टिक नहीं पाया, परिणामत: जीडीपी अवस्फीतिकारक न्यनतम स्तर पर पहुँच गई, वस्तुत: विकास एवं ब्याज दरों के बीच अंतर उन्मूलन हुआ। और समस्या इसी मे निहित है ।

1.76 परिणास्वरूप, राजकोषीय दृष्टिकोण इस बात पर टिका होता है कि ब्याज विकास अंतर में क्या परिवर्तन होते हैं। यदि यह सामान्य होते हैं तो बिना समायोजन उपायों के ऋण - जीडीपी अनुपात अपने आप नीचे आ जाता है। उदाहरण के लिये, यदि न्यूनतम विकास की तेजी से पुन:पूर्ति होती है और यह अगले पांच वर्षों तक औसत 12 प्रतिशत रहता है (कहने का मतलब है, वास्तविक लगभग 8 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति) जबकि सरकारी ऋण पर प्रभावी ब्याज दर मौजूदा स्तरों पर रहती है तब समेकित ऋण अगले पांच वर्षों तक जीडीपी के 1.5 प्रतिशतता बिन्दुओं तक नीचे आता है-अपितु राज्य विद्युत सुधार योजना 'उदय' के अधीन जीडीपी के लगभग ढ़ाई प्रतिशत के आसपास ऋण की उम्मीद करें। चूंकि राज्य केवल अपने मौजूदा देनदारियों को ही स्वीकार करते हैं और इसे अपने बैलेंस सीट (लेखा-जोखा) में लाते हैं, राजकोषीय प्रगति को चिन्हित करने का बेहतर तरीका यह होगा कि उदय बॉण्डों के सिवाय ऋण में कटौती की जाए। यह जीडीपी का 4 प्रतिशत होगी (चित्र 13 एवं 14)

1.77 तथापि, इस परिदृश्य के फलीभूत होने का विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होगी। एक बात तो यह है कि प्रतिकूल झटके ऋण संबंधी गति को मार्ग से हटा सकते हैं। वैश्विक पुनरूद्धार डगमगा सकता है। मुद्रास्फीति संभावना से कम हो सकती है। इन कारणों के साथ-साथ कई अन्य कारणों से भी, ब्याज वृद्धि संबंधी विभेदक के जल्द सामान्य होने की संभावना नहीं है।

1.78 परिणामस्वरूप अधिक विवेकपूर्ण तरीका यह होगा कि अनुमानित स.घ.उ. के अधिक क्रमिक पुनरूद्धार का पूर्वानुमान किया जाए, जैसे कि जहां अनुमानित वृद्धि अगले पांच वर्षों में औसतन 11 प्रतिशत रहे। उस मामले में, ब्याज-वृद्धि संबंधी विभेदक ऋण को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा-प्राथमिक घाटा कम किए जाने की जरूरत होगी। लेकिन यदि ऐसी कार्यनीति अपनाई जानी थी तो साधारण और क्रमिक समायोजन भी बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे। मिसाल के तौर पर, यदि राजकोषीय घाटे में प्रतिवर्ष स.घ.उ. के लगभग 0.2-0. 3 प्रतिशतांक की कमी की जाती तो अवधि के अंत तक समग्र घाटा लगभग 3 प्रतिशत रहता और प्राथमिक घाटा मूलत: समाप्त हो जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्काल नहीं तो आखिरकार ऋण अनुपात में गिरावट होगी। ऋण में समग्र तौर पर स.घ.उ. के 2 प्रतिशत अंक की गिरावट होगी और बुनियादी संदर्भ में 4.5 प्रतिशतांक की गिरावट होगी, जो अधिक अनुकूल वृद्धि के परिदृश्य के मुकाबले कुछ अधिक ही होगा (चित्र 14 में, यह परिदृश्य ''ऋण-ज'' में जो दर्शाया गया है, उसके काफी निकट रहेगा) और बेशक, यदि

[8] *d* refers to public liabilities of the general government; *pd* refers to primary deficit; *i* is the interest rate and *g* is the growth rate.

चित्र 13 : विकास ब्याज दर अंतर

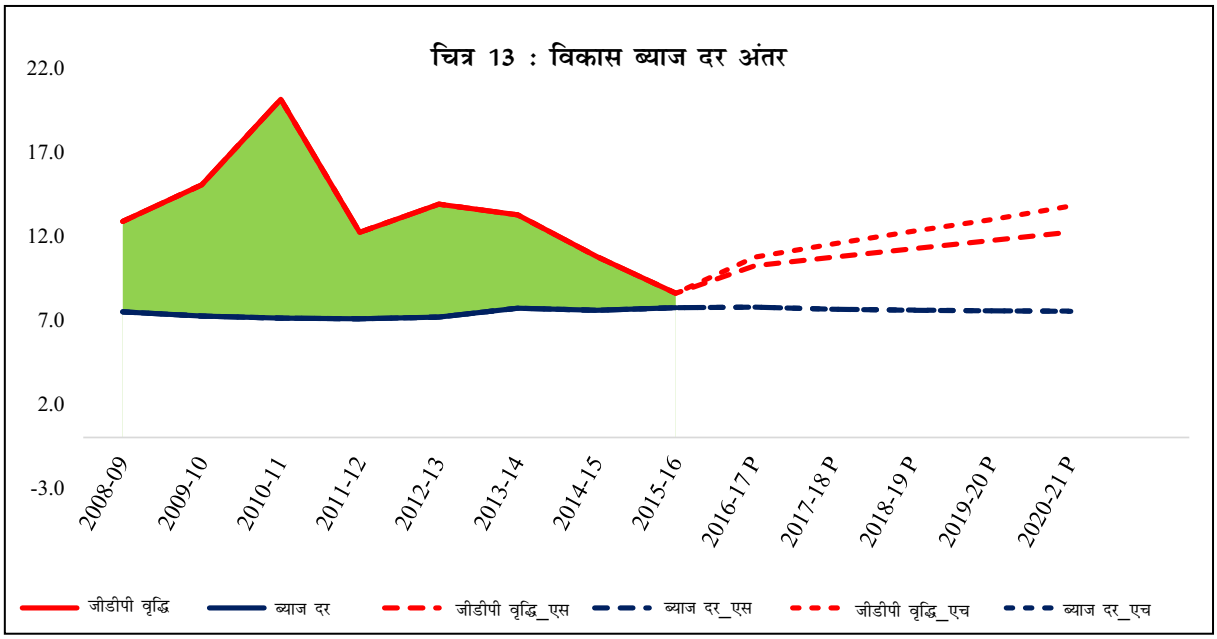

***स्रोत:* सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक और पूर्वानुमान**

प = पूर्वानुमानित
जीडीपी वृद्धि _ एस = धीमी जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान
जीडीपी वृद्धि _ एच = उच्चत्तर जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान
ब्याज दर _ एस = धीमी जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के अंतर्गत पूर्वानुमानित ब्याज दरें
ब्याज दर _ एच = उच्चत्तर जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के अंतर्गत पूर्वानुमानित ब्याज दरें

चित्र 14: सामान्य सरकार और केंद्र सरकार की ऋण संबंधी गति

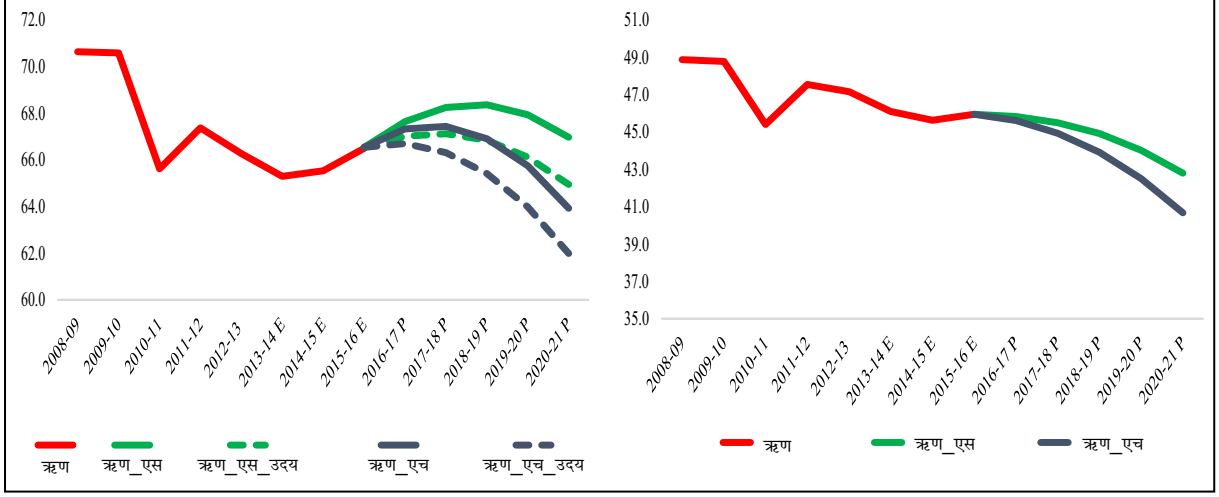

***स्रोत:* सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक, डीएमओ, बजट दस्तावेज और पूर्वानुमान**

अ = अनुमानित प = पूर्वानुमानित
ऋण _ एस = धीमी जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण
ऋण _ एस _ उदय = धीमी जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण और उदय
ऋण _ एच = उच्चतर जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण
ऋण _ एच _ उदय = उच्चतर जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण और उदय रहित

अ = अनुमानित प = पूर्वानुमानित
ऋण _ एस = धीमी जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण
ऋण _ एच = उच्चतर जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के तहत ऋण

अर्थव्यवस्था राजकोषीय विवेक और अपनाए जा रहे अन्य संरचनागत सुधारों के प्रति अनुक्रियाशील हो और विकास पहले के स्तरों पर लौट आए, तो ऋण में होने वाली गिरावट और भी अधिक होगी।

1.79 कुल मिलाकर, राजकोषीय नीति को साइला और शेरिबडिस के बीच बनाए रखने की जरूरत है। जैसाकि पहले कहा गया था, सक्रिय राजकोषीय समेकन की कार्यनीति के पक्ष में अच्छे तर्क हैं और अभी भी कमजोर पुनरूद्धार को नकारात्मक मांग से जुड़े बड़े झटके से बचते हुए भी, ऋण को वहनीय मार्ग पर डालने वाले साधारण समेकन की कार्यनीति के लिए भी अच्छे तर्क हैं। केंद्रीय बजट में इन विकल्पों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा।

1.80 बहरहाल, मध्यावधिक राजकोषीय फ्रेमवर्क की समीक्षा का समय आ गया है। व्यय संबंधी आयोजना के संदर्भ में मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य आवश्यक है। जब से 14 वें वित्त आयोग मध्यावधिक राजस्व अनुमान उपलब्ध कराएं तब से बुनियादी विकास और राजकोषीय संभावनाओं में बड़े परिवर्तन हो गए हैं। और, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि विश्वभर में मध्यावधिक राजकोषीय फ्रेमवर्क के संबंध में नए दृष्टिकोण अपनाए गए हैं और इनमें नई घटनाएं भी हुई हैं जिनसे भारत उपयोगी सीख ले सकता है।

वैदेशिक संभावनाएं

1.81 विगत वर्ष की समीक्षा में प्रधान मध्यमकालिक जोखिम के रूप में कमजोर विदेशी माहौल को चिह्नित किया गया था। यह लघुकालिक जोखिम भी साबित हुआ और अनुमान है कि यह आगामी अवधि में ऐसा ही बना रह सकता है।

1.82 इस वर्ष की एक उलझन रही है कि तेल की कीमतों में और जिन देशों में भारतीय कामगार काम करते हुए ठहरे हैं उन देशों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट के बावजूद विप्रेषण उतना ही क्यों बना हुआ है (चित्र 15)। भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा अर्जन विप्रेषण प्रवाह में गिरावट नहीं होने के कारण बेहतर रही। फिर भी, विवेक की मांग पर आय के इस स्रोत का अनुवीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सुखद स्थिति है कि निकट भविष्य में तेल की कीमतों के कम रहने के कारण तेल निर्यातक देश अंततः सांयोगिक रूप से बाध्य होकर विदेशी श्रम के उपयोग में कटौती कर देंगे।

1.83 तेल निर्यात प्रथम 3 तिमाहियों में लगभग 18 प्रतिशत घट गया; ऐसा अधिकांश वस्तुओं की गिरती कीमतों के कारण हुआ, परंतु गैर तेल डालर निर्यात और निर्यात मात्रा में ह्रास अभी भी पर्याप्त था। वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात 2006-2011 (चित्र 8) के दौरान लगभग 17 प्रतिशत की औसतन वृद्धि की तुलना में प्रथम 3 तिमाहियों में स्थिर बना रहा। परिणामतः इस वर्ष की वृद्धि विगत वर्ष की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 1-1.2 प्रतिशत अंकों से पिछड़ गई। आगे बढ़ रही संभावना के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस हालिया निर्यात निष्पादन का प्रधान कारण वैश्विक मांग में कमी है या विनिमय दर अथवा अन्य कारकों से संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी है।

चित्र 15: केरल से खाड़ी देशों तक विप्रेषण और विमान यात्री परिवहन

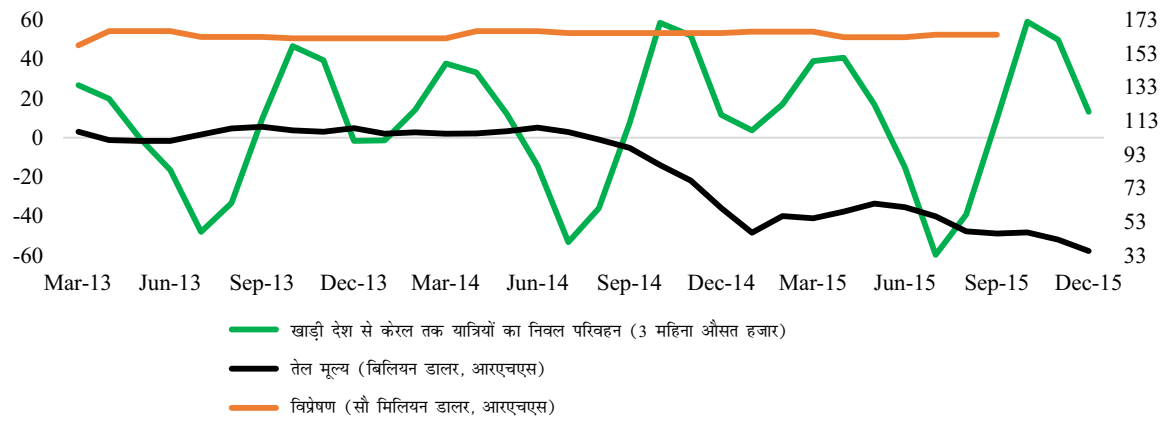

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और डीजीसीए

1.84 यह सुवर्णित है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को नुकसान हुआ है और ऐसा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हुआ है। अत: प्रश्न यह है कि क्या भारत का निष्पादन अन्य निर्यातकों से खराब रहा है।

1.85 हम यह जांच करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि वैश्विक निर्यातों की तुलना में वैश्विक जीडीपी के संदर्भ में भारतीय निर्यात ने किस तरह का निष्पादन किया है। चित्र 16 से चार प्रकार के संबंध प्रतिबिम्बित हैं: माल के भारतीय निर्यात और वैश्विक जीडीपी के बीच (शीर्ष वाम पैनल); भारतीय सेवा निर्यात और विश्व जीडीपी के बीच (शीर्ष दायां पैनल); और विश्व के लिए दो समकक्ष (अवतल पैनल)। यह द्रष्टव्य है कि 2000 के दशक में, भारत निर्मित मालों और सेवाओं का निर्यात सर्वोत्तम रेखा से ऊपर था, परंतु ध्यान दें कि सेवा का निष्पादन विनिर्माण से अधिक रहा (सेवा आंकड़ा बिंदु विनिर्माण आंकड़ा बिंदु की रेखा से अधिक ऊपर है)। विश्व के लिए, समान परंतु अल्प् घोषित पैटर्न विशेषकर सेवा के मामले में है। तथापि, विगत दो वर्षों में, भारतीय सेवा निर्यात भारतीय विनिर्माण निर्यात एवं वैश्विक सेवा निर्यात से अधिक प्रभावित रहा है।

1.86 अन्य दृष्टि से, विनिर्माण निर्यात पर सारा जोर रहने के कारण उस तथ्य से ध्यान हट गया है जो कोई कम महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है। भारतीय सेवा निर्यात ने ही अधिकांश महत्वपूर्ण रूप से, और शायद ध्यानाकर्षक रूप में बदलाव किया है। हम बाजार शेयरों को देखते हुए इस समस्या को समझ सकते हैं। 2000 के दशक के मध्य में, उछाल के बाद, वैश्विक सेवा निर्यात में भारतीय हिस्सा शिथिल हो गया है।

1.87 जिस तथ्य से यह घटनाक्रम उलझ जाता है वह यह है कि हालिया वर्षों में भारतीय सेवा निर्यात की संरचना भारतीय विनिर्मित मालों के निर्यात से अधिक अनुकूल है। पहले का अधिकांश हिस्सा संयुक्त राज्य में जाता है और दूसरे का अधिकांश हिस्सा एशिया को जाता है। चूंकि एशिया में द्रुत रूप से मंदन हुआ है, अत: भारत के विनिर्माण विषयक निर्यात पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, विगत वर्ष में डालर के

चित्र 16: निर्यात और विश्व का सकल घरेलू उत्पाद

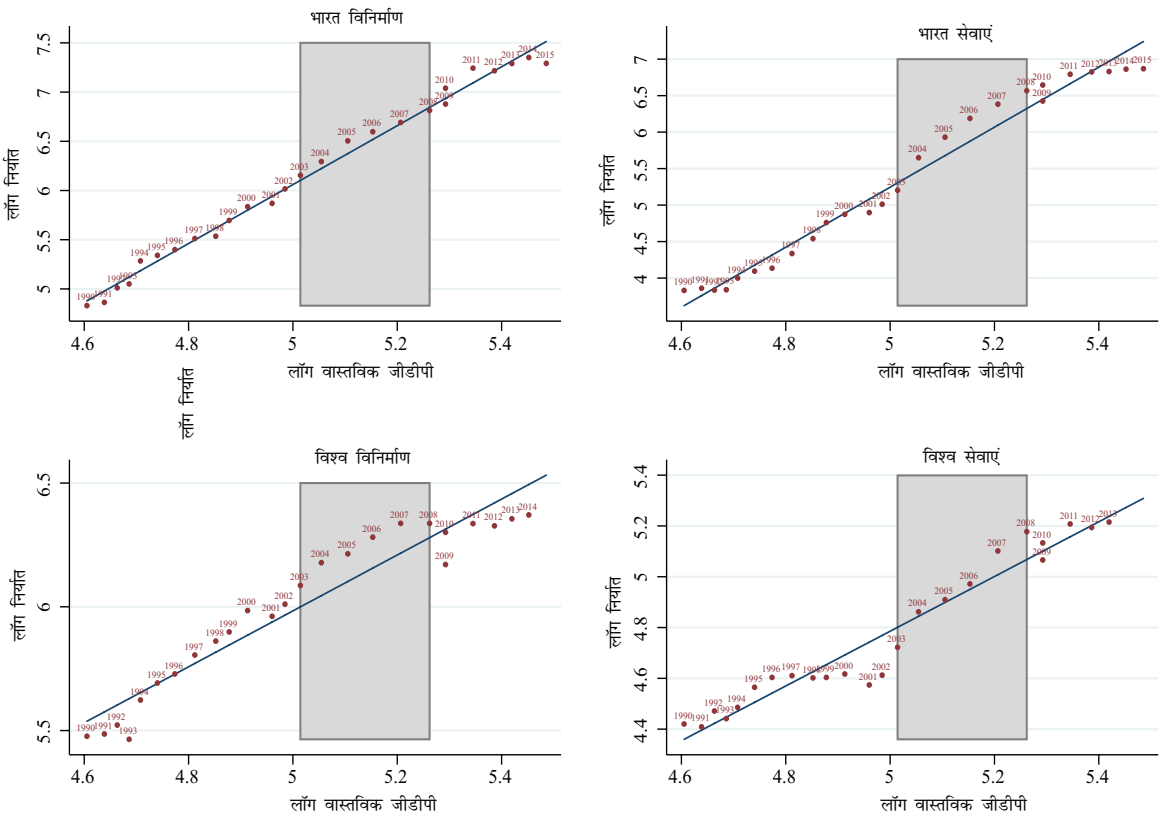

विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात का ब्योरा क्रमश: विश्व बैंक विनिर्माण एकक मूल्य सूचकांक तथा अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर का प्रयोग करके तैयार किया गया है।

मुकाबले रुपए का अत्यधिक मूल्यह्रास हुआ है जिससे भारतीय सेवा निर्यात में मदद मिलनी चाहिए थी।

1.88 इन गतिविधियों के दीर्घावधि निहितार्थ है। भारत की मध्यावधि वृद्धि की संभावना 8.10 प्रतिशत को मानते हुए तीव्र निर्यात वृद्धि आवश्यक होगी। इसकी गति कितनी तीव्र हो, इसका सुझाव वृद्धि में उछाल की तुलनात्मक अवस्था में विनिर्माण में चीन के कार्यनिष्पादन के साथ सेवाओं में भारत के निर्यात कार्यनिष्पादन की तुलना करके दिया जाना चाहिए।

चित्र 17 में 1991 की शुरूआत में, विनिर्माण निर्यात में चीन के वैश्विक बाजार हिस्से और 2003 के प्रारंभ में, जब मोटे तौर पर शेयर समान ही थे, भारत के वैश्विक बाजार हिस्से पर इसके प्रभाव को निरूपित किया गया है। इस चुनौती का परिमाण और भी सुस्पष्ट हो जाता है जब गत 15 वर्षों में चीन के विकास पथ की जांच की जाती है। समान पथ को हासिल करने के लिये भारत की प्रतिस्पर्धात्मिकता को बेहतर बनाना होगा ताकि इसके सेवा निर्यात, वर्तमान में विश्व निर्यात का लगभग 3 प्रतिशत, का हिस्सा विश्व बाजार के हिस्से का लगभग 15 प्रतिशत हो जाए। यह एक बड़ी चुनौती है-तथा हालिया रूझान सुझाते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए सुधर रही प्रतिस्पर्धात्मकता में बड़े प्रयास करने होंगे।

व्यापार नीति

1.89 दशकों से, व्यापार के संबंध में भारत की बुनियादी स्थिति संपूर्ण राजनैतिक वर्णक्रम में, बुद्धिजीवियों के मत की व्यापक रेंज के हिसाब से सामान्य रही है। लेकिन इस अवधि के दौरान, अर्थव्यवस्था में लगभग मान्यता से अधिक परिवर्तन हुआ है। नैरोबी विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं की असफलता, वृहत क्षेत्रीय व्यापार करारों के कारण अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना में जबरदस्त परिवर्तन, एक ऐसी मंदी वाली अर्थव्यवस्था जो राष्ट्रीय आम राय के आसपास सामूहिक रूप से आत्मचिंतन करने हेतु एक बड़े अवसर के साथ वर्तमान भारत को घरेलू उद्योग से जोड़ने पर दबाव डालती है।

1.90 निम्न पांच मुद्दों का आत्मावलोकन अपेक्षित है:

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के आलोक में किसानों को सहायता प्रदान करना;
- कृषक प्रोत्साहनों पर त्रृटिपूर्ण व्यापार नीति के प्रभाव का उपशमन करना;
- व्यापार वार्ताओं में भारत के लिये बाधक ''बड़ी किन्तु घटिया'' दुविधा का समाधान करना;
- विदेशी माहौल द्वारा डाले जा रहे दबावों से निपटना; और
- व्यापार के संबंध में विश्व के साथ और व्यापक रूप से लगना ।

कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन

1.91 सबसे पहले, दोहा विकास कार्यसूची के दो महत्वपूर्ण मुद्दों से शुरूआत करना: विशेष सुरक्षोपाय तंत्र (एसएसएम) और खाद्य सुरक्षा/सरकारी हितधारिता, ये दोनों किसानों के हितों को प्रभावित करतें हैं।

चित्र 17: विश्व विनिर्माण और सेवा निर्यात में भारत और चीन का हिस्सा (प्रतिशत)

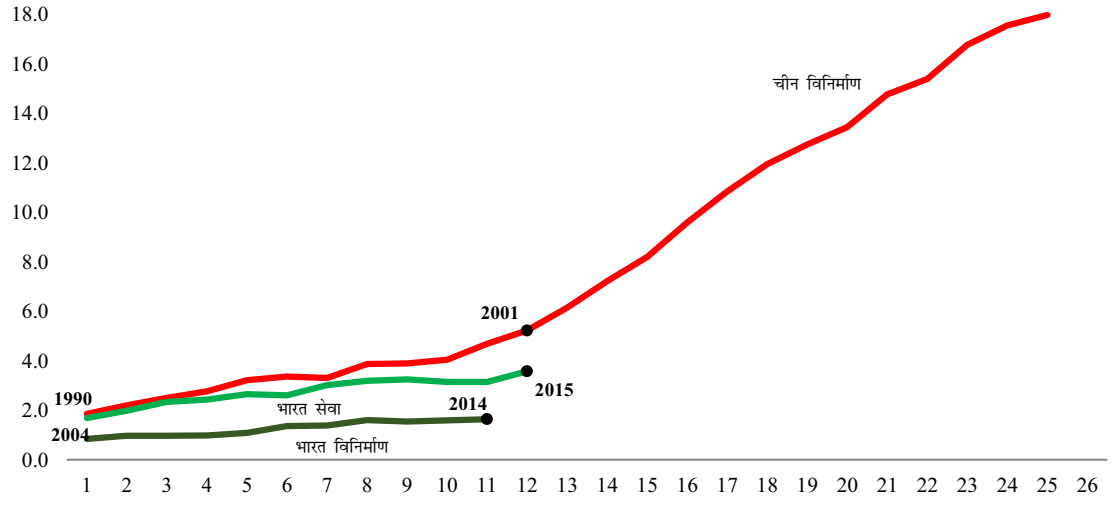

1.92 विशेष सुरक्षोपाय तंत्र भारत में कृषि आयातों में वृद्धि होने पर व्यापार अवरोधक लागू करने के अधिकार को मूर्तरूप देता है। किन्तु एक महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा किया गया प्रश्न यह है कि: भारत को विशेष सुरक्षोपाय तंत्र की किस सीमा तक आवश्यकता है? उरूग्वे दौर में, भारत सहित अनेक देशों को अधिकतम सीमा (बहुत अधिक हेतु सीमा) प्रशुल्क बाध्यताएं निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी: अर्थात् उन्हें, विश्व व्यापार संगठन की अपनी बाध्यताओं के रूप में, प्रशुल्कों के उच्च स्तर, जो 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत (कृषि में भारत की मॉडल दर)से 150 प्रतिशत के बीच निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। प्रशुल्क रेखाओं की प्रधानता में, लागू प्रशुल्कों तथा प्रशुल्क बाध्यताओं के बीच काफी अंतर है।

1.93 एक बार भारत के पास यह स्वतंत्रता होने के बाद, रक्षात्मक कार्रवाई करना आवश्यक नहीं था क्योंकि आयात बढ़ने के प्रत्युत्तर में ही नहीं बल्कि अन्यथा भी, भारत बाध्यता की उच्च सीमा तक प्रशुल्क बढ़ा सकता था। तो फिर क्यों, लंबे समय तक, भारत एसएसएम लगाने का अधिकार मांग रहा है, जो असल में कृषि नीतियों के निर्धारण के लिए और भी अधिक स्वतंत्रता की मांग करना है?

1.94 उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसा कि तालिका 2 दर्शाती है कि भारत की प्रयुक्त दर, प्रशुल्क लाइनों के लगभग 4 प्रतिशत के लिए बाध्य दर के 5 प्रतिशत से कम, और इसकी प्रशुल्क लाइनों के लगभग 16 प्रतिशत के लिए 20 प्रतिशत से कम है। इसलिए, भारत की एसएसएम के लिए एकमात्र वास्तविक जरूरत इसकी प्रशुल्क लाइनों – कुछ दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, कुछ फलों और कच्चे खालों के एक छोटे से अंश के संबंध में उत्पन्न होती है – जहां इसकी प्रशुल्क बाध्यताएं 10-40 प्रतिशत के बीच में है जो आयात बढ़ने की स्थिति में भारत के विकल्प को सीमित करते हुए असुविधाजनक रूप से भारत के चालू प्रशुल्कों के करीब हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो भारत को एसएसएम पर चर्चा के लिए सिद्धांत के एक सामान्य मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि कृषि प्रशुल्कों के एक छोटे से हिस्से को शामिल करते हुए एक व्यावहारिक वार्ता उद्देश्य के रूप में मांग करनी चाहिए। कदाचित, इस दृष्टांत में, स्वतंत्रता और संप्रभुता के बारे में दिव्य धर्मशास्त्र बघारने के कार्य की बजाय, चर्म और गुड़हर पर व्यावहारिक मोलभाव करना चाहिए।

1.95 अब खाद्य सुरक्षा/स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे को लें। भारत ने 2014 में एक वास्तविक कच्चा-लोहा कानूनी गारंटी प्राप्त की थी, जिसने बाली निर्णय को स्थायी कर दिया और इसे एक ठोस कानूनी आधार प्रदान किया था। इसे नैरोबी में दोहराया गया था। यह सवाल अभी बना हुआ है कि क्या किसी ''स्थायी समाधान'' के लिए दबाव डालना वास्तविक रूप से आवश्यक है।

1.96 विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में संकुचन के समय में, भारत को अपने किसानों को सहायता प्रदान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सहायता के उचित स्तर और समर्थन के तरीके पर दृष्टिकोण शेष है। विशेष नीतियां जिनका बचाव किया जा रहा है, ये वे नीतियां हैं जिसमें से भारत उनके पूरी तरह से प्रलेखित प्रभावों: जल स्तर में कमी; बिजली और उर्वरकों के अधिक प्रयोग (स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है), और फसल के बाद डंठल जलने के कारण बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से किसी भी तरह से बाहर निकलने का इरादा रखता है। इसके अलावा, सरकार किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता और फसल बीमा प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

1.97 कृषि और विश्व व्यापार संगठन पर आगे का मार्ग निम्नलिखित वैचारिक संदर्भ में सोचा जा सकता है। उरुग्वे दौर के समय, भारत खाद्य का शुद्ध आयातक था और इसने फैसला किया कि इसे 'सीमा सुरक्षा' (विशेष रूप से प्रशुल्क) बनाए रखने के लिए काफी अधिक अवसर की जरूरत है और यह घरेलू समर्थन (उत्पादक सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि) के माध्यम से कृषि को सहायता प्रदान करने के बारे में कम चिंतित था। यही भारत का विकल्प था।

1.98 बीस वर्षों के बाद, कृषि के क्षेत्र में भारत की स्थिति बदल गई है: यह कृषि के क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है और अब यह घरेलू उत्पादन को बनाए रखने और किसानों की कम आय दोनों के समाधान हेतु कृषि के लिए घरेलू सहायता (और प्रशुल्क संरक्षण पर कम) पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहता है। भारत के विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों में घरेलू सहायता के लिए सीमा सुरक्षा से दूर यह वांछनीय और कम विकृत

बदलाव प्रतिबिंबित होना चाहिए। भारत को अपनी बहुत ही उच्च प्रशुल्क बाध्यताओं में कमी की पेशकश पर विचार करना चाहिए और इसकी बजाय घरेलू सहायता का उच्च स्तर प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए; यह विशेष रूप से दालों के लिए आगे बढ़ने हेतु सही होगा जहां दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक हो सकता है। यह भारत के लिए अच्छा होगा, और भारत के व्यापारिक साझेदारों को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए और अधिक तर्कसंगत होना चाहिए।

परिवर्तनशील व्यापार नीति

1.99 कृषि नीति, विशेष रूप से व्यापार नीति, की विशेषता असामान्य उतार-चढ़ाव है। उतार-चढ़ाव आश्चर्यजनक रहे हैं। इस खंड के तकनीकी परिशिष्ट में तालिका 1क में दर्शाए गए कपास के मामले को ही देखें। 2010 में, इस नीति में दस परिवर्तन हुए थे जो अधिकतर निर्यात से संबंधित थे और जो अक्सर पिछली कार्यवाहियों के विपरीत थे। 31 मार्च, 2011 की कार्रवाई की तुलना में 4 अगस्त, 2011 की कार्रवाई को देखें। तत्समय 2011 में 5, 2012 में 5 और 2014 में 2 परिवर्तन हुए थे।

1.100 कृषि के क्षेत्र में यह मत है कि उत्पादक और उपभोक्ता के हितों को संतुलित किया जाना है। जब विश्व में कीमतें ऊपर जाती है या घरेलू कमी होती है तो निर्यात प्रतिबंध या निषेध लगाए जाते हैं; जब स्थिति विपरीत होती है तो आयात प्रशुल्क लगाए जाते हैं। लेकिन नीति में इस उतार-चढ़ाव से वास्तव में किसानों (नि:संदेह) किन्तु अंतत: उपभोक्ताओं को भी नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि किसान नीति में उतार-चढ़ाव के कारण कम उत्पादन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम घरेलू उपलब्धता के कारण कीमतें अधिक बढ़ जाती हैं। किसान न केवल इस तथ्य से प्रभावित होते हैं कि उनको अपनी उपज के लिए औसतन कम राशि मिलती है, बल्कि उससे भी अधिक वे नीति की अनिश्चितता के कारण प्रभावित होते हैं जो उत्पाद के प्रोत्साहन को कम करती है, यहां तक कि निरुत्साहित भी करती है। यह धारणा कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कारोबार का कोई संबंध नहीं है, बहुत कम समय के अलावा, गलत है।

1.101 कृषि नीति - न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा आयात और निर्यात नीति - की फसल उगाने के मौसम से काफी पहले घोषणा की जानी चाहिए और मौसम के दौरान इसे बदला नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई असाधारण घटनाएं न हों।

व्यापक मुद्दे: 'बड़ा-किन्तु-निर्धन दुविधा

1.102 भारत को दो व्यापक मुद्दों की पकड़ से बाहर निकलने की जरूरत है। पहले को 'बड़ा-किन्तु-निर्धन' दुविधा कहा जा सकता है। एक तरफ, भारत की गरीब देश के रूप में स्व-धारणा पारस्परिक आदान-प्रदान को मानने और अमल में लाने की अनिच्छा को व्यक्त करती है। दूसरी ओर, भारत की नीतियों का वैश्विक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जिसमें साझेदार देशों का बाजार में प्रवेश मांगने का एक वैध अधिकार है - जैसा कि भारत का उसके साझेदारों के बाजार के संबंध में होना चाहिए।

1.103 बाद वाले कथन का अर्थ यह है कि साझेदार, भारत से पारस्परिक आदान-प्रदान करने की उम्मीद करते हैं: 'आप अपने बाजार खोलें और/या हमारे ऐसा करने के बदले में आप रक्षा करने की अपनी स्वतंत्रता को कम करें।' यदि बड़े व्यापारिक देशों के क्षेत्रीय समझौतों के लिए इससे निर्णायक रूप से दूर होने के मद्देनजर विश्व व्यापार संगठन को अप्रासंगिकता में नहीं धकेला जाना है तो केवल एक ही रास्ता है: भारत, चीन और अन्य देशों को अपने बाजारों को खोलने की पेशकश करनी चाहिए और अपने व्यापार साझेदारों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के बदले में विश्व व्यापार संगठन के साथ भविष्य की वार्ता के संदर्भ में और अधिक प्रतिबद्धता का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

1.104 1970 और 1980 के दशकों में, विश्व व्यापार संगठन में भारत की वचनबद्धता मौटे तौर पर गैर-पारस्परिक थी। यह संभव था क्योंकि इस गैर-पारस्परिकता का आकार काफी अल्प होने के चलते, करोबार भागीदारों ने इसे नजरअंदाज किया था। आज वे भारत के बाजार के आकार की वजह से वे इसकी परवाह करते हैं, और भारत को ''बड़ा-किन्तु-निर्धन'' दुविधा को संतुलित करते हुए जवाब देना चाहिए।

1.105 भागीदार देशों को पुनरूद्धार बहुपक्षवाद में गंभीर रूचि प्रकट करनी चाहिए। समान रूप से, भारत और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने के लिए व्यापारिक साझेदारों हेतु स्वयं को आकर्षक बनाना चाहिए। इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से के

लिए भारत को और अधिक पारस्परिक आदान-प्रदान का व्यवसाय करने और श्रम की गतिशीलता सहित विदेशों में अपने स्वयं के बाजार हितों को प्राप्त करने का लाभ उठाने हेतु अपने बढ़ते बाजार का उपयोग करना आवश्यक होगा।

1.106 अनिच्छुक वचनबद्धता की कीमत की ध्यानपूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है। अमेरिका और दूसरे देश करारों (ट्रांस पैसिफिक साझेदारी (टीपीपी)) पर वार्ता कर रहे हैं जिससे भारत को बाहर रखा गया है और इसलिए इसने एक ऐसा रूप ले लिया है जो भारत के महत्वपूर्ण हितों (बौद्धिक संपदा पर नियम अच्छे उदाहरण हैं) को ध्यान में नहीं रखता है। जब कभी भारत इन करारों में शामिल होता है तो यह भारत की शर्तों पर नहीं बल्कि पहले से ही तैयार शर्तों पर होगा, वे शर्तें जिन्हें भारत प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि उसे रचनात्मक तरीके से भाग लेना नहीं माना जाएगा।

वर्तमान तनाव से निपटना

1.107 व्यापार नीति अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में चल रही उथल-पुथल से संबंधित कारणों से भी तनाव में है। वैश्विक मांग कमजोर है, और हाल के समय में व्यापार की महाशक्तियों में से एक - चीन - की विकास गति धीमी हो रही है। चीन की गिरावट से भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अन्य देशों से गति प्रतिक्रिया स्थापित होते हुए जैसे-जैसे चीन की मुद्रा कमजोर पड़ेगी, भारत की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता सीधे-सीधे दबाव में आ जाएगी। लेकिन इसके क्षेत्रीय प्रभाव भी होंगे। इस्पात और एल्यूमिनियम जैसी वस्तु से संबंधित क्षेत्रों में चीन की अतिरिक्त क्षमता से भारत में आयात में वृद्धि होगी।

1.108 भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? भारत को संरक्षणवादी उपायों का सहारा लेने से बचना चाहिए, विशेष रूप से उन मदों के संबंध में जो अनुप्रवाह कंपनियों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकते हैं। इसकी बजाय, इसे तीन तरीकों से जवाब देना चाहिए। पहला, समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता के खतरों का जवाब देने का सबसे प्रभावी साधन विनिमय दर है। रुपए के सुदृढ़ीकरण से परिहार करते हुए, इसकी कीमत उचित होनी चाहिए। इसे मौद्रिक शिथिलता के कुछ संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि यदि पूंजी प्रवाह कमजोर है तो रुपए में क्रमिक गिरावट की अनुमति देना, यदि अंतर्वाह मजबूत है तो विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना; और ऐसे अंतर्वाह के आगे और व्यापक होने के बारे में सतर्क रहना जो रुपए को मजबूत कर सके।

1.109 दूसरा, भारत को उन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना चाहिए जो विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप हों और पाटन (प्रतिपाटन), सहायता (प्रतिकारी शुल्क), और आयातों में वृद्धि (रक्षोपायों) के खिलाफ शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से वैध कार्यवाहियां की जा सकें। अप्रभावी घरेलू प्रक्रियाओं का खतरा व्यापक आधार वाली संरक्षणवादी कार्यवाहियों के लिए बहाना बन सकता है।

1.110 तीसरा, भारत को उन सभी नीतियों को खत्म करना चाहिए जो वर्तमान में भारतीय विनिर्माण को नकारात्मक सुरक्षा प्रदान करती हैं और विदेशी विनिर्माण का समर्थन करती हैं। इसे जीएसटी के शीघ्र कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जैसी कि जीएसटी समिति की ताजा रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। यदि विलंब की परिकल्पना की गई है तो प्रतिकारी शुल्क में छूट को समाप्त करके समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

व्यापक मुद्दे: व्यापार आरंभ करने के लिए पूर्वापेक्षाएं

1.111 इन सभी निकटवर्ती मुद्दों को अंतर्निहित करना गंभीर समस्या है: क्या व्यापार उदारीकरण केवल सेवाओं के लिए ही नहीं अपितु कृषि और विनिर्माण को आगे ले जाने के लिए भी दक्षता, गतिशीलता और विकास का एक स्रोत हो सकता है?

1.112 इसे और अधिक स्पष्ट रूप से पेश करने, और उन शब्दों में जिनका रोड्रिक और सुब्रमण्यम (2004)[9] 1980 और 1990 के दशक के भारत के आर्थिक सुधारों का वर्णन करने के लिए प्रयोग करते थे: क्या भारत वास्तव में प्रतियोगिता समर्थक है या यह केवल व्यापार समर्थक है?

1.113 प्रत्येक देश, और प्रत्येक देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अधिक निर्यात चाहता है। लेकिन आयातों के बारे में भी काफी अधिक दुविधा है। तथापि, व्यापार का दक्षता प्रभाव घरेलू उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा में उजागर करके और निर्यात क्षेत्रों की ओर संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए घरेलू स्तर पर प्रोत्साहनों का सृजन करके आयात के माध्यम से कार्य करता है।

---

[9] Dani Rodrik and Arvind Subramanian, *From Hindu Growth to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition,*" NBER Working Paper No.10376

1.114 अब, मंथन, तनाव और विस्थापन से और अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिसमें कुछ अप्रतिस्पर्धी कंपनियां और उद्योग बाहर निकलने पर विवश हो जाएंगें।व्यापर उदारीकरण की अन्तर्वर्ती लागतों को स्वीकारना और लक्षित सहायता के रूप में, उन्हें झेलने के लिए व्यवस्था करना, भारत के लिए जरूरी होगा ताकि वह आज डब्ल्यूटीओ में तथा, यदि भारत ऐसा फैसला करता है तो भविष्य में ट्रांसपैसिफिक भागीदारी में विश्वसनीय तरीके से वार्ता कर सके। यही कारण है कि सरकार की स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पहल इतने महत्वपूर्ण हैं। व्यापार को और अधिक व्यापक करने से पाई के आकार में वृद्धि होगी लेकिन यह सभी को बेहतर बनाने के लिए अवस्थांतरण चरण में सहायता से युक्त होना चाहिए।

1.115 कुछ मायनों में, व्यवधान और प्रस्थान की घरेलू राजनीति से उत्पन्न होने वाले अधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा के बारे में वह दुविधा विश्व व्यापार संगठन, व्यापार समझौतों, और अधिक व्यापक तौर पर व्यापार नीति के साथ भारत की कठिनाइयों के केन्द्र में है (जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई है)। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है।

तालिका 2: कृषि में भारत की वास्तविक और बाध्य दर (प्रतिशत)

प्रयुक्त के बिना बाध्य	प्रशुल्क लाइनों की संख्या	संचित प्रशुल्क लाइन	प्रतिशतता	संचित
0	21	21	1.6	1.6
1-5	20	41	1.5	3.1
6-10	136	177	10.4	13.5
11-20	39	216	3.0	16.4
21-30	109	325	8.3	24.7
31-40	354	679	26.9	51.7
41-60	111	790	8.4	60.1
61-80	235	1025	17.9	78.0
81-100	101	1126	7.7	85.7
100 से अधिक	188	1314	14.3	100.0
कुल	**1314**			

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन